सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 186, नई दिल्ली, शनिवार 13 सितम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।"

03 भाजपा ने 'दिल्ली में कूड़े को आजादी' अभियान चलाया - अंकुश नारंग

06 बाजरा बनाम क्विनोआ: वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है?

08 'स्वास्थ्य पर चर्चा': अमृतसर में अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने जागरूकता पर दिया जोर

नेपाल में जारी आपदा के बीच फंसे भारतीय ट्रकों और चालकों की सुरक्षा एवं वापसी की मांग:

भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला-"उफत्सा" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) की ओर से हम नेपाल में वर्तमान आपदा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। नेपाल में सितंबर 2025 में जारी सिविल अनरेस्ट, जिसमें छात्रों द्वारा सरकारी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ने पूरे देश में अशांति पैदा कर दी है। इस अशांति में अब तक 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, और सेना की तैनाती की गई है। इसके अलावा, भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिसमें 9 सितंबर 2025 तक पिछले 24 घंटों में 15 आपदाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें भूस्खलन, भारी वर्षा, बिजली गिरना और आग शामिल हैं। इन घटनाओं ने नेपाल में परिवहन और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है, विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा वर्ती क्षेत्रों पर।

इस संकट के बीच, हजारों भारतीय ट्रक नेपाल में फंसे हुए हैं, जो माल ढुलाई के लिए वहां गए थे। ये ट्रक मुख्य रूप से निर्माण सामग्री, खाद्य पदार्थ, लौह और अन्य आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे थे, लेकिन अशांति और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वे सुरक्षित रूप से वापस नहीं लौट पा रहे हैं। नेपाल में सितंबर 2024 के समान भारी वर्षा घटना ने लगभग 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित किया था, जिसमें 270 से अधिक मौतें हुईं और 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। वर्तमान स्थिति में भी इसी प्रकार की चुनौतियां हैं, जहां जुलाई 2025 तक तीन महीनों में नेपाल में 93 मौतें और 22 लापता मामले दर्ज किए गए हैं, मुख्य रूप से बाढ़ से।इनमें से कई घटनाएं भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों जैसे रसुवागढ़ी में हुई हैं, जहां 8 जुलाई 2025 को एक विनाशकारी बाढ़ ने सीमा पारगमन को प्रभावित किया।

उफत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी की ओर से हम भारत सरकार से निम्नलिखित मांगें तथ्यात्मक आधार पर रखते हैं:

ट्रकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी: नेपाल में खड़े सभी भारतीय ट्रकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा ली जाए। वर्तमान अशांति में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा ने 16 मौतें कर दी हैं, जिससे ट्रक चालकों और वाहनों को खतरा है। सरकार द्वारा राजनयिक स्तर पर नेपाल सरकार से समन्वय कर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

ट्रकों की वापसी की व्यवस्था: फंसे हुए सभी भारतीय ट्रकों को तत्काल वापस लाने की व्यवस्था की जाए। सीमा पर विशेष एस्कॉर्ट और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किए जाएं, ताकि चालक और वाहन सुरक्षित भारत लौट सकें।

लोड गाड़ियों का सुरक्षित अनलोडिंग: लोडेड ट्रकों में मौजूद माल को सुरक्षित रूप से अनलोड कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि नुकसान से बचा जा सके और व्यापारिक हानि कम हो। नेपाल में फंसे माल की कीमत करोड़ों में है, और आपदा के कारण अनलोडिंग में देरी हो रही है।

फंसी गाड़ियों की वापसी: नेपाल के अंदर फंसी सभी भारतीय गाड़ियों को तुरंत वापस मंगाया जाए विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उड़ीसा,हरियाणा,राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की अधिकांश गाड़ियां फंसी हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूस्खलन ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे ट्रक चालक फंसे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर या वैकल्पिक मार्गों से सहायता प्रदान की जाए।

विशेष राहत पैकेज की घोषणा: नेपाल आपदा में फंसे सभी गाड़ी मालिकों और चालकों के लिए आपदा राहत के तहत विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए। इसमें आर्थिक सहायता,बीमा कवरेज,ई एम आई डिडक्शन और नुकसान की भरपाई शामिल हो। जुलाई 2025 तक की आपदाओं में बाढ़ से 137 घटनाएं दर्ज हुईं, जिससे ट्रांसपोर्ट उद्योग को भारी नुकसान हुआ है।

ये मांगें ट्रक ट्रांसपोर्ट उद्योग की वास्तविक चुनौतियों पर आधारित हैं, जो भारत-नेपाल व्यापार पर निर्भर है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की जाए,ताकि चालकों की जान बचाई जा सके और आर्थिक नुकसान रोका जा सके। यदि आवश्यक हो तो सरकारी प्रोटोकॉल के तहत हम घटनास्थल पर जाने को भी तैयार हैं अन्यथा मांगे अनसुनी होने पर मुद्दे आधारित धरना विभिन्न राज्यों मे या अन्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

यमुनापार में तय किए गए 18 नए बस रूट, आईआईटी दिल्ली की मदद से लास्ट माइल कनेक्टिविटी में होगा सुधार

आईआईटी दिल्ली की मदद से यमुना पार क्षेत्र में 18 नए बस रूट चिन्हित किए गए हैं। यह रूट रेशनलाइजेशन योजना डीटीसी के तीन डिपो - ईस्ट विनोद नगर शास्त्री पार्क और गाज़ीपुर से शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना ट्रैफिक जाम को कम करना और दिल्ली मेट्रो सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

नईदिल्ली। आईआईटी दिल्ली की तकनीकी सहायता से रूट रेशनलाइजेशन के बाद राजधानी यमुना पार क्षेत्र में 18 नए बस रूट चिन्हित किए गए हैं।

इससे डीटीसी बसों की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी और मेट्रो रूटों से बसों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

योजना के अंतर्गत डीटीसी के तीन प्रमुख बस डिपो– ईस्ट विनोद नगर, शास्त्री पार्क और गाजीपुर से कई नए रूट की पहचान की गई है।

ईस्ट विनोद से ये 11 रूट किए तय

रूट रेशनलाइजेशन के जरिए ईस्ट विनोद नगर डिपो से 11 रूट तय किए गए हैं। इनमें पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से प्रियदर्शनी विहार, गणेश नगर से शास्त्री पार्क मेट्रो, कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन से न्यू मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया, उस्मानपुर-2 पुश्ता से मंडोली जेल रोड हैं।

इनमें साथ ही आनंद विहार आईएसबीटी से अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, मयूर विहार फेज़-वन से मयूर विहार मेट्रो स्टेशन, गीता कॉलोनी से मानसरोवर पार्क मेट्रो, आईपी एक्सटेंशन मेट्रो से न्यू अशोक नगर, ईस्ट आजाद नगर से ताहिरपुर क्रॉसिंग, प्रीत विहार मेट्रो से प्रीत विहार और न्यू अशोक नगर मेट्रो से न्यू अशोक नगर मेट्रो कनेक्टिविटी शामिल है।

शास्त्री पार्क से चार रूट डिजाइन किए

इसी तरह शास्त्री पार्क बस डिपो से चार रूट डिजाइन किए गए हैं। इसमें सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से शिव विहार, मौजपुर-बाबरपुर से करावल नगर टर्मिनल, गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से सभापुर गांव, और मौजपुर-बाबरपुर से मौजपुर-बाबरपुर मेट्रो कनेक्टिविटी स्टेशन शामिल है।

गाजीपुर से तीन नए बस रूट प्रस्तावित

गाजीपुर बस डिपो से तीन नए रूट प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें गाज़ीपुर डेयरी फार्म से मयूर विहार फेज- वन मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो से हर्ष विहार जेल रोड और अशोक नगर एक्सटेंशन से मेट्रो स्टेशन तक है।

सभी मार्गों को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यह लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ सकें जिससे सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को भी कम किया जा सके। साथ ही न्यू मंडोली, पटपड़गंज और ताहिरपुर जैसे औद्योगिक केंद्रों को सीधी बस कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

योजना के जरिए बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, कनेक्टिविटी में सुधार कर दिल्ली के सुदूर इलाकों को जोड़कर दिल्ली मेट्रो सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जिससे अधिक से अधिक लोग डीटीसी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़ सकें।

परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि डीटीसी को पर्यावरण के अनुकूल जिम्मेदार इकाई बनाने के साथ ही सहज मोबिलिटी पर फोकस करने के लिए बीते छह महीनों में ही डीटीसी के बेड़े में 3,800 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है।

इससे दिल्ली के लगभग 40 लाख बस यात्रियों को फायदा मिल रहा है। इन सुधारों के जरिए हमारी सरकार का मकसद दिल्ली परिवहन निगम को घाटे से उबारकर लाभप्रद संस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

रूट रेशनलाइजेशन के स्वीकृत रूट को दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि सार्वजनिक परिवहन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।

डॉ. लॉजिस्टिक्स – वैश्विक व्यापार की समझ से भारत की आर्थिक शक्ति तक

डॉ. अंकुर शरण

परिचय: डॉ. लॉजिस्टिक्स एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं और पेशेवरों को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की जटिलताओं को समझने में मदद करना है। यह मंच अनुभवी विशेषज्ञों और नई पीढ़ी के बीच संवाद स्थापित कर, व्यापार जगत की व्यावहारिक जानकारी साझा करता है। इसका लक्ष्य है – वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी को मजबूत करना और युवाओं को उद्योग के लिए आवश्यक कौशल से सशक्त बनाना।

आज के अतिथि: इस सत्र में हमारे साथ हैं सुशांत भटनागर, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे देश की अग्रणी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में शिपिंग, सेल्स और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कस्टम्स प्रक्रियाओं, डॉक्युमेंटेशन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ग्राहक सेवा में उनकी गहरी समझ उन्हें उद्योग का एक भरोसेमंद नाम बनाती है। उनका अनुभव न केवल व्यापारिक रणनीतियों को मजबूत करता है, बल्कि युवाओं को करियर के सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स – भारत के लिए क्यों जरूरी है?

भारत का व्यापार विश्व के कई देशों से जुड़ा है। निर्यात और आयात की प्रक्रिया तभी सुचारू रूप से चलती है, जब समय पर माल की ढुलाई, लागत का संतुलन और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित हो। शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रबंधन इन सभी में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इससे न केवल उद्योग को गति मिलती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को बेहतर बनाता है।

ज्ञान साझा करना – उद्योग की सबसे बड़ी आवश्यकता

व्यापार जगत में केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, सही जानकारी और अनुभव की साझा प्रक्रिया ही युवाओं को उद्योग के लिए तैयार करती है। कई बार प्रक्रियाओं, दस्तावेजीकरण, कस्टम्स नियमों और वैश्विक मानकों की जानकारी न होने से युवा अवसरों से वंचित रह जाते हैं। अनुभवी पेशेवरों द्वारा मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के माध्यम से युवाओं को आत्मविश्वास मिलता है, जिससे वे बेहतर करियर विकल्प चुन सकते हैं।

शुरुआती दौर की चुनौतियाँ

सुशांत भटनागर बताते हैं कि करियर की शुरुआत में नेटवर्क का अभाव, दस्तावेज़ों की जटिलता, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और ग्राहकों का भरोसा जीतना बड़ी चुनौतियाँ थीं। वैश्विक व्यापार की बारीकियों को समझने में समय लगा, लेकिन लगातार सीखने और सही मार्गदर्शन से वे आज उद्योग में मजबूती से स्थापित हैं। उनका मानना है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे आत्मविश्वास और विशेषज्ञता बढ़ती है।

करियर का नया क्षितिज – लॉजिस्टिक्स और शिपिंग युवाओं के लिए क्यों हैं बेहतरीन अवसर

आज का समय बदल रहा है। डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स, वैश्विक व्यापार और तेज़ वितरण सेवाओं ने व्यापार की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे में लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब सिर्फ एक सहायक कार्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और नेतृत्वकारी क्षेत्र बन चुका है। यह युवाओं के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ते करियर विकल्पों में से एक है। आइए समझते हैं कि क्यों:

✓ तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग

भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। निर्यात-आयात, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए लॉजिस्टिक्स पेशेवरों की मांग आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ेगी।

✓ वैश्विक अवसर

इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी करियर बनाने का अवसर मिलता है। शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों, एयर फ्रेट, वेयरहाउस, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, कस्टम्स और फॉरवर्डिंग जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र मिलता है।

✓ बहुआयामी करियर विकल्प

इस क्षेत्र में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि डेटा विश्लेषण, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डॉक्युमेंटेशन, ग्राहक सेवा, योजना, जोखिम प्रबंधन जैसे कई विभागों में करियर बन सकता है। युवाओं को अपनी रुचि और कौशल के अनुसार काम चुनने की स्वतंत्रता मिलती है।

✓ उच्च वेतन और स्थिरता

जैसे-जैसे उद्योग का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे विशेषज्ञ पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को आकर्षक वेतन, बोनस, अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट और करियर ग्रोथ के भरपूर अवसर मिल रहे हैं।

✓ तकनीकी और नवाचार से जुड़ाव

आधुनिक लॉजिस्टिक्स में ऑटोमेशन, AI आधारित पूर्वानुमान, ब्लॉकचेन, IoT, और डेटा-आधारित निर्णय लेने की तकनीकों का उपयोग हो रहा है। यह क्षेत्र तकनीक से जुड़े युवाओं के लिए आदर्श मंच है, जहाँ वे नई खोजों और समाधान विकसित कर सकते हैं।

✓ समस्या समाधान और नेतृत्व का मौका

इस क्षेत्र में रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाना, रणनीतियाँ बनाना और टीम का नेतृत्व करना प्रमुख कार्य हैं। इससे युवाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल और आत्मनिर्भरता का विकास होता है।

✓ समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान

लॉजिस्टिक्स और शिपिंग का सही संचालन न केवल व्यापार को मजबूत करता है, बल्कि आपूर्ति की कमी, महंगाई, ऊर्जा बचत, समय प्रबंधन जैसे मुद्दों को भी हल करता है। इस क्षेत्र में काम कर युवा देश की आर्थिक प्रगति में सीधे योगदान देते हैं।

युवाओं के लिए प्रेरक सुझाव

सीखने की प्रक्रिया को अपनाएँ और जानकारी की तलाश में बने रहें।

कस्टम्स, डॉक्युमेंटेशन और अंतरराष्ट्रीय नियमों की समझ विकसित करें।

नेटवर्किंग को अपनी ताकत बनाएं – उद्योग से जुड़ें, संपर्क बनाएं।

असफलताओं से सीखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें।

तकनीकी बदलावों, डेटा विश्लेषण और ई-कॉमर्स से खुद को अपडेट रखें।

पारदर्शिता और नैतिकता को अपनी पहचान बनाएं।

डॉ. लॉजिस्टिक्स – बदलते भारत का नया चेहरा

डॉ. लॉजिस्टिक्स युवाओं और पेशेवरों के बीच की दूरी को कम कर, व्यापार जगत की जटिलताओं को सरल भाषा में समझाने का मंच बन चुका है। यह पहल न केवल उद्योग को प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार के केंद्र में लाने की दिशा में प्रेरक भूमिका निभा रही है। यह स्पष्ट है कि भविष्य का भारत मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और बेहतर लॉजिस्टिक्स के बल पर वैश्विक व्यापार में अपनी अहम पहचान बनाएगा।

यह लेख युवाओं के लिए न केवल प्रेरणा है, बल्कि एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ भी है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स की दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। डॉ. लॉजिस्टिक्स ऐसे संवादों के माध्यम से एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नए आयाम देगा।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://forms.gle/VEThcFgMcknGFc1u9

TEMPLE OF LIBERALIZATION AND SOCIAL WELFARE ALLIED TRUST REGT.

MEMBERSHIP FORM FOR TOLWA TRUST

transportvisheshcontent@gmail.com Switch account

The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form

* Indicates required question

How you got aware about TOLWA trust *

- Social Media
- News Paper
- Personal connection
- Youtube
- Social Function/ RTO/friends/family

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय:- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ मानते हैं

क्या आप जानते हैं ?

माँ कामाख्या मंदिर और तंत्र का गहरा और अद्भुत संबंध है।

आइए जानते हैं माँ कामाख्या के अद्भुत रहस्य और मंदिर का तंत्र से संबंध;

माँ कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किमी दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहां न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्वीर। बल्कि यहां एक कुंड है, जो हमेशा ही फूलों से ढंका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी के योनी भाग की पूजा होती है।

धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां-जहां यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता का योनी भाग गिरा था, इसलिए यहां उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनी की पूजा होती है। आज यह जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गादेऊल, बसंती पूजा, मदान देऊल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है।

।।कामाख्या मंदिर और तंत्र का संबंध।।

1. मूल शक्ति स्थलः- कामाख्या पीठ को ₹तंत्र की राजधानी₹ कहा जाता है।

यहाँ माता सती का योनि और गर्भस्थान गिरा था, जो सृजन शक्ति और प्रकृति की मूल ऊर्जा का प्रतीक है।

इसलिए तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का यह सर्वोच्च स्थान माना जाता है।

2. तांत्रिक परंपराः- इस मंदिर में साधक काली, तारा, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, और कमला – इन दस महाविद्याओं की आराधना करते हैं।

यहाँ वामाचार तंत्र (जिसमें शक्ति को भोग और त्याग दोनों के माध्यम से साधा जाता है) की परंपरा प्रचलित रही है।

तंत्र में कामाख्या को सर्वोच्च साधना स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ की शक्ति सीधी और अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है।

3. अंबुवासी मेला (रजस्वला पर्व):- यह मेला तांत्रिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

मान्यता है कि इस समय माँ कामाख्या को मासिक धर्म होता है।

तीन दिन मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और चौथे दिन खुलते हैं।

यह सृजन शक्ति का प्रतीक है और तांत्रिक इसे प्रकृति की काम-शक्ति और ऊर्जा का पर्व मानते हैं।

4. गूढ़ साधनाएँ:- कामाख्या में भैरव और भैरवी साधना, तंत्र-मंत्र, अघोरी साधना, शक्ति उपासना और काम-तंत्र विशेष रूप से की जाती हैं।

यहाँ की साधना में प्रकृति और शक्ति का मिलन ही मोक्ष और सिद्धि का मार्ग माना जाता है।

कुछ साधक यहाँ कपाल साधना, शव साधना, और तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्ति और आत्मोन्नति होता है।

5. तांत्रिक महत्वः- कामाख्या को ₹कामरूप₹ भी कहा जाता है, क्योंकि यह काम (इच्छा), क्रिया और शक्ति का केंद्र है।

तांत्रिक मान्यता है कि जो यहाँ साधना करता है, उसे अष्टसिद्धि और नव निधि प्राप्त हो सकती है।

यहाँ की तांत्रिक शक्ति इतनी प्रबल मानी जाती है कि इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक स्थल कहा जाता है।

जिनका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्ति और आत्मोन्नति होता है।

समुंद्र_ऋषि_का_मुखाकृति_विज्ञान______

आज का भारत कुछ भी हो लेकिन निसंदेह अतीत का भारत विद्या की खान "विश्व गुरु "था शायद ही ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां ग्रंथ लेखन व अनुसंधान ना हुआ हो.. |

आज हम चर्चा करेंगे महाभारत काल के पश्चात हुए समुंद्र ऋषि व उनके अनुसंधानआत्मक कार्यों के विषय में... एक ऐसा ऋषि जिसने दुनिया को इंसानी चेहरे को पढ़ना सिखाया ..चेहरा मनुष्य के मन का दर्पण होता है इस वाक्य को आधार बनाकर समुंद्र ऋषि ने समुंद्रशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की... 12 भागों में लिखा गया यह ग्रंथ चेहरे के हावभाव रचना के आधार पर व्यक्ति के चरित्र स्वभाव को परिभाषित करता है... आज समुंद्र ऋषि के कार्य को हमने तो विस्मृत कर दिया लेकिन पश्चिम ने उसे सम्मान पूर्वक स्वीकृति देते हुए मुखाकृति विज्ञान की संज्ञा दी है जिसे फिजियोजनॉमी (physiognomy)बोला जाता है | ऑक्सफोर्ड कैंब्रिज में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होता है... आपको आश्चर्य होगा अमेरिका व दुनिया की की शीर्ष अन्वेषण संस्था Federal Bureau of Investigation(FBI)समुंद्र ऋषि के सिद्धांतों का ही इस्तेमाल करती है दुर्दांत अपराधियों संदेहास्पद गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आकलन के लिए.... समुंद्र ऋषि ने इंसानी चेहरे को 8 भागों में व्यक्त किया... माथे की सलवटो त्योरी के चढ़ने, ठोड़ी की हलचल जैसे 27 बिंदुओं से वह व्यक्ति चरित्र तात्कालिक मनो स्थिति का विश्लेषण करते थे इसी प्रकार चेहरे को पढ़ने की अनोखी युक्तियां विकसित कि मनुष्य के अंतर्मन में क्या चल रहा है किस बोध से वह ग्रस्त है... समुंद्र ऋषि के मुखाकृति विज्ञान की स्थापना से आज का कपाल विज्ञान (phrenology) समुंद्र ऋषि की देन है जिससे मानव नर विज्ञानियों जिन्हें एंथ्रोपॉलजिस्ट कहा जाता है उनको भी मदद मिलती है.. चिकित्सा विज्ञान में भी इस्तेमाल होता है... मानस रोगों की चिकित्सा के लिए... सचमुच हमारे ऋषि अनूठे थे जिन्होंने वेद ज्ञान के आधार पर उसकी व्याख्या कर विद्या के अनेक क्षेत्रों की स्थापना की... आज ज्ञान के मामले में हमारी हालत किसी से छिपी नहीं है महाभारत के भीषण संग्राम ने इस देश को ऐसी क्षति दी है जिसकी क्षतिपूर्ति शायद ही कभी हो पाए...|

आपने भी देखा होगा गांव कुटुंब परिवार के अनुभवी बुजुर्ग परिवार के छोटे सदस्य की मनो स्थिति का यथार्थ विश्लेषण कर लेते थे... भूला भटका उन्हें यह ज्ञान या स्किल अल्प मात्रा मैं विरासत में मिला.. फलित ज्योतिष वालों ने इस विज्ञान को दुरुपयोग किया इसके आधार पर मनुष्य के भाग्य को गढ़ने लगे जिससे पाखंड फैला... !

यदि तन मन धन से पुरुषार्थ किया जाए ऐसी अनेक लुप्त हो चुकी विद्याओं को विश्व पटल पर पुनः स्थापित किया जा सकता है... वंदे भारत विश्व गुरु भारत के खोखले नारों से काम नहीं चलेगा... !

अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करने से मिलते है 6 लाभ

आयुः पुत्रान्यशः स्वर्ग कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियम्।
पशुन्सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयातपितृपूजनात।।
(यमस्मृति, श्राद्धप्रकाश)

यमराजजी का कहना है कि श्राद्ध करने से मिलते हैं ये 6 पवित्र लाभ :-

श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है।

पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं।

परिवार में धन-धान्य का अंबार लगा देते हैं।

श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल-पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है।

पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन-धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं।

श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है।

सुख-दुख दाएं-बाएं खड़े हैं...!

एक दीप आस का जलाए रखना,
यह जिंदगी हँसी है बनाए रखना।
गुलशन में फूल खिलेंगे रहमत है,
कांटों का चमन मिला किस्मत हैं।

गमों की तपन अंदर झूलसाती हैं,
सुख की बौछार इतराके आती है।
इसे बनाए रखने का हुनर सीखो,
सभी हमेशा मुस्कुराते हुए दिखों।

बस जीना नहीं खुल के जीना है,
मीठा जहर 'हँस' के उसे पीना है।
जिंदगी के इम्तिहान बहुत बड़े हैं,
सुख-दुख देखो दाएं-बाएं खड़े हैं।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक

प्रेम पच्चीसा
(भाग 25)

राजेन्द्र रंजन गायकवाड़
सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक
बिलासपुर,छत्तीसगढ़

शेरुखान ने हनी के तलाक की पूरी सच्चाई संस्था के सामने रखी तो संस्था ने खान और उनके पूरे परिवार को संस्था अनेक काम लगा दिया। आदर्श समाज संस्था में शामिल होकर सोचा रहा है कि अब उनके परिवार की ज़िंदगी संवर जाएगी।। शेरुखान को संस्था के ऑफिस में सिलाई प्रशिक्षक होने साथ- साथ गांवों में जाकर लोगों को संस्था की योजनाओं के बारे में बताना और सदस्यता दिलाना था।

संस्था में सब ठीक लग रहा था। हनी अब कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक बन चुकी थी और उसकी कमाई से घर में थोड़ी राहत आई थी। माया जो एक अमीर बिजनेसवुमन थीं, ने न सिर्फ बुटीक का सारा सामान खरीदा था, बल्कि हनी को अपनी कंपनी में सहायक बनाकर उसे नई जिंदगी दी थी। खान परिवार अब गरीबी की दलदल से बाहर निकल चुका था, लेकिन शेरुखान के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि वो अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधारें ?

एक दिन, संस्था की मीटिंग में शेरुखान ने बताया कि —बलरामपुर में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है जिस को बेचकर वो बच्चों को शहर बसाना चाहते हैं, लेकिन गॉंव के परिवार वाले ज़मीन अपना कब्ज़ा कर चुके हैं। शेरु खान के नाम की ज़मीं भी नहीं बेचने दे रहें है। रोहन ने समझाया कि आपसी समझौता कर लीजिए। लेकिन सामने वाले खान के परिजन समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे।

धीरे-धीरे पारिवारिक संघर्ष शुरु हो गया। गाँव के लोगों के उकसाने पर गुंडे शेरुखान को धमकाने लगे। एक रात, जब शेरुखान घर लौट रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वे घायल हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। हनी ने सुना तो वह माया के पास गई। माया, जो खुद एक संघर्षशील महिला थीं, ने हनी को सलाह दी, "तुम्हारे पापा सही हैं। हमें सबूत इकट्ठा करके पुलिस और मीडिया तक पहुंचना होगा।" हनी ने अपने कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल किया और संस्था के कुछ गुप्त दस्तावेज़ हैक करके (कानूनी तरीके से, एक दोस्त की मदद से) सबूत जुटाए। पता चला कि गॉंव के रिश्तेदारों ने पहले भी कई गरीबों को ठगा था।

माया और रोहन के सहयोग से शेरुखान ने हिम्मत जुटाई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां उन्होंने अपने रिश्तेदार और गाँव के गुंडों की पोल खोल दी। मीडिया में हंगामा मच गया। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। शेरु खान ने जमीन बंटवारे का मसला कोर्ट में फाइल कर दिया। खान के रिश्तेदारों ने शेरुखान के परिवार को धमकी दी कि पूरे परिवार का नेस्तनाबूत कर देंगे। लेकिन जीत सत्य की होती है कुछ माह बाद कोर्ट का फैसला खान के पक्ष में आ गया और वो अपने हिस्से की जमीन बेचकर अपने बच्चों को लेकर शहर आकार किराये से रहने लगा। उनके तीनों बेटे भी सिलाई, कढ़ाई और मार्केटिंग के अच्छे जानकार हैं, हनी और उसकी छोटी बहिन कौशर भी अपनी पढ़ाई के साथ एनजीओ के काम के साथ घर का काम करते रहते।

कई महीनों के संघर्ष के बाद, खान परिवार न सिर्फ़ ग़रीबी से मुक्त हुआ, बल्कि समाज में एक मिसाल बन गया। हनी की सगाई एक ईमानदार युवक से हुई, और शेरुखान ने सोचा, "ज़िंदगी के संघर्ष हमें मजबूत बनाते और सिखाते हैं कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती पर जीत सच्चाई की होती है।

(भाग २६)

"यूपी-80 ए क्राइम स्टोरी" का पोस्टर हुआ लॉन्च, इसी माह ओटीटी पर होगी रिलीज

ग्लोबल ताज इंटरनेशनल व खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में मिल चुके हैं प्रतिष्ठित पुरस्कार

₹हमारा उद्देश्य न केवल बेहतरीन सिनेमा प्रस्तुत करना है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करना है – फिल्म निर्माता सावन चौहान

बहुत जल्द हमारी आने वाली फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर भी कार्य आरंभ होने जा रहा है – फिल्म निर्माता सावन चौहान

आगरा, संजय साग़र सिंह। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी आगरा एक बार फिर फिल्मी चमक से रोशन हो उठी जब नवोदित फिल्म निर्माता सावन चौहान द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर ₹यूपी-80 ए क्राइम स्टोरी₹ का पोस्टर आज़ संजय प्लेस स्थित चाइनीज़ कैफे में धूमधाम से लॉन्च किया गया। फिल्म इसी माह एक प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाएगी।

इस फिल्म का निर्माण सावन सिने क्रिएशन और ए. जी. ड्रीम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के संयुक्त बैनर तले किया गया है। फिल्म का निर्देशन अंकित गोला ने किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के युवा फ़ल्मि निर्माता की भूमिका में सावन चौहान हैं।

स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास

कार्यक्रम के दौरान फिल्म निर्माता सावन चौहान ने कहा, ₹हमारा उद्देश्य न केवल बेहतरीन सिनेमा प्रस्तुत करना है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करना है। बहुत जल्द हमारी आने वाली फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर भी कार्य आरंभ होने जा रहा है।₹

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहले ही बटोर चुकी है सराहना

गौरतलब है कि यह फिल्म वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड तथा खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है, जो इसकी गुणवत्ता और प्रभावशाली प्रस्तुति का प्रमाण है।

दिग्गज कलाकारों की दमदार उपस्थिति

फिल्म में बॉलीवुड के अनुभवी चरित्र अभिनेता दीपक शर्मा वत्स ने खलनायक की सशक्त भूमिका निभाई है, वहीं नायक के रूप में जतिन सूर्यवंशी दर्शकों को अपनी अदाकारी से प्रभावित करेंगे।

नायिका की भूमिका में सोनाली पांडे और श्वेता सिंह नज़र आएंगी, जबकि वरिष्ठ अभिनेता रमेश गोयल ने न्यायाधीश की भूमिका निभाई है। रंगमंच से जुड़े कलाकार उमाशंकर मिश्र फिल्म में वकील के रूप में नजर आएंगे।

विशेष उल्लेखनीय बात यह रही कि फिल्म में आगरा व आसपास के क्षेत्रों के अनेक स्थानीय कलाकारों ने भी सशक्त भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें श्वेता सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।

इस अवसर पर अभिनेता दीपक शर्मा वत्स ने बृज क्षेत्र की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, ₹हमारे यहां ऐसे कलाकारों की भरमार है जिन्होंने टेलीविजन, बॉलीवुड, भोजपुरी व साउथ फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी है। सरकार को चाहिए कि इन उभरती प्रतिभाओं के लिए संरक्षक नीतियाँ बनाकर उन्हें सशक्त बनाए।"

कार्यक्रम में रही लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी

पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार महेश धाकड़, सत्यम गुप्ता, सुनील राज, डी. के. अश्वनी, विनोद बघेल (समाजसेवक), पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार, फिल्मप्रेमी और दर्शक उपस्थित रहे।

सेब खाने के लाभ

सेब पौष्टिक तत्वों से भरा है। ये न केवल बीमारियों से लडने में मदद करता है बल्कि आपको शरीर हैल्दी रखता है। सेब में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सेब को खाने से पाचन तंत्र भी सही रहता है। यह एक अच्छा एंटीओक्सिडेंट भी है। जो कैंसर, मधुमेह से संबंधित जैसी बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है।

1.एनीमिया को करें दूर ये एनेमिया जैसी बीमारी का इलाज भी करता है क्योंकि सेब में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप दिन में 2-3 सेब खाते हैं तो यह पूरे दिन की आयरन की कमी को पूरा करता है।

2.सेब पित्तनाशक, वातनाशक, पुष्टिकारक ह्रदय एवं गुर्दो के लिए लाभकारी है। पथरी के रोगी के लिए सेब बहुत फायदेमंद है। रोगी को चार से पांच सेब प्रतिदिन खाने चाहिए।

3.फीवर आने पर रोगी को प्यास, थकान, पेट में जलन तथा बहुत बेचैनी रहती है तो ऐसे में सेब का रस बहुत फायदेमंद साबित होता है।

4.सेब पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे पेट में गैस नहीं बनती एवं पेट में कीडे भी पैदा नहीं होते। दो मीठे सेब या सेब का एक गिलास ताजा रस रोजाना पीने से पेट के कीडों से राहत मिलती है एवं कब्ज की शिकायत भी दूर होती है।

5.बढे वजन के कारण मधुमेह, उक्त रक्तचाप, ह्रदय रोग जैसी बीमारियों से राहत दिलाने में सेब का सेवन फायदेमंद होता है। सेब में पर्याप्त मात्रा में मौजूद फाइबर वजन कम करने में मदद करता है।

6.तनाव व काम के कारण रात को नींद न आती हो तो सोने से पहले मीठे सेब का मुरब्बे के साथ गुनगुना दूध पीएं। रात को बिना किसी टेंशन अच्छी नींद आयेगी।

7.बेहोशी, सिरदर्द, चिडचिडापन या उन्माद की शिकायत से ग्रस्त व्यक्ति को खाने से पहले दो मीठे सेबों का सेवन करना चाहिए।

8.जिन लोगों को पुरानी खांसी हो तो उन्हें प्रतिदिन सुबह एक गिलास सेब के रस मिश्री मिलाकर पीना चाहिए।

(१) संन्यास किसे कहते हैं?

(१) संन्यास किसे कहते हैं?

किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना।

(२) संन्यासी कैसा होना चाहिये ?

रागरहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि-असिद्धि में निर्विकार होना चाहिये।

(3) संन्यास का साधन कैसा होना चाहिये ?

सात्त्विकी बुद्धिवाला, वैराग्यवान्, एकान्त का सेवन करने वाला, इन्द्रियों का नियमन करनेवाला, शरीर-वाणी-मनको संयत करनेवाला आदि होना चाहिये।

(४) संन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिये ?

कर्तृत्वाभिमान और राग-द्वेष से रहित होकर कर्म करना।

(५) संन्यासी का भाव कैसा होना चाहिये ?

सम्पूर्ण विभक्त प्राणियों में विभागरहित एक परमात्मतत्त्व को देखना।

(श्रीमद्भगवतगीता, अध्याय १८, ११०२)

मुस्कान भी नकली, चेहरा भी: AI बना रहा है झूठी तस्वीरें

--- संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

आज की दुनिया में तस्वीरें सिर्फ़ यादें सहेजने का जरिया नहीं रह गईं, बल्कि पहचान, विश्वास और सच्चाई का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी हैं। लेकिन अब इस सच्चाई पर एक गहरा साया पड़ चुका है। डिजिटल क्रांति के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने जब से फोटो एडिटिंग के नए टूल्स दिए हैं, तब से तस्वीरें हकीकत की बजाय झूठ का चेहरा बनने लगी हैं। मुस्कान नकली हो सकती है, चेहरा किसी और का हो सकता है और पहचान इतनी बदली जा सकती है कि असलियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए। यही है आधुनिक तकनीक का नया और डरावना चेहरा। पहले फोटो एडिटिंग का मतलब होता था हल्का-फुल्का बदलाव—रंग-रूप निखारना, दाग-धब्बे हटाना या बैकग्राउंड बदलना। लेकिन एआई ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह उलट-पुलट कर दिया है। अब किसी की तस्वीर को इस हद तक बदला जा सकता है कि असली और नकली के बीच की रेखा मिट ही जाती है। यह बदलाव सिर्फ़ सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह किसी व्यक्ति की पूरी पहचान को नया रूप देने की ताकत रखता है। कोई भी चेहरा किसी और के चेहरे से मिलाया जा सकता है, किसी की आवाज़ के साथ उसका वीडियो तैयार किया जा सकता है और इस तरह डीपफेक जैसी तकनीकें दुनिया भर में भय का कारण बन चुकी हैं।

सोशल मीडिया के युग में यह खतरा और भी बढ़ गया है। जहां पहले लोग अपनी असली तस्वीरों से पहचान बनाए रखते थे, वहीं अब नकली प्रोफ़ाइल्स का एक विशाल बाज़ार तैयार हो गया है। कई लोग एआई से बनाई गई आकर्षक तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट बनाते हैं, ताकि धोखाधड़ी की जा सके। डेटिंग ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल स्कैम—हर जगह इन नकली तस्वीरों का दुरुपयोग हो रहा है। लोग किसी पर भरोसा करके रिश्ते या लेन-देन शुरू करते हैं और बाद में समझ पाते हैं कि सामने वाला चेहरा असल में कभी था ही नहीं। यह सिर्फ़ व्यक्तिगत धोखाधड़ी तक सीमित नहीं। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी एआई से बदली गई तस्वीरें और वीडियो एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहे हैं। चुनावी मौसम में नेताओं के डीपफेक वीडियो वायरल किए जाते हैं, जिनमें वे ऐसी बातें कहते या करते दिखते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं। इस तरह मतदाताओं को गुमराह करना आसान हो जाता है। किसी आंदोलन, दंगे या घटना से जुड़ी नकली तस्वीरें फैलाकर माहौल को भड़काना भी अब बेहद आसान हो गया है। एक क्लिक से फैलाया गया यह झूठ सैकड़ों-हजारों लोगों तक तुरंत पहुंच जाता है और कई बार असली सच्चाई सामने आने से पहले ही नुक़सान हो चुका होता है।

समस्या यह भी है कि आम लोग अब तस्वीरों पर भरोसा करना छोड़ रहे हैं। पहले किसी घटना का सबूत तस्वीरें और वीडियो हुआ करते थे, लेकिन अब हर सबूत पर शक की गुंजाइश बनी रहती है। अदालतों से लेकर अख़बारों तक और आम बातचीत से लेकर शोध तक—हर जगह यह सवाल उठने लगा है कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, वह असली है या एआई से बनाई गई? इस संदेह ने पत्रकारिता, न्यायपालिका और विज्ञान जैसे गंभीर क्षेत्रों में भी नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। निजता पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी की तस्वीर लेकर उसमें बदलाव कर सकता है। खासकर महिलाओं के मामले में यह खतरा कहीं ज्यादा बढ़ा है। कई बार उनकी तस्वीरें लेकर एआई से अश्लील रूप में बदला जाता है और फिर ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाया जाता है। यह साइबर क्राइम का नया और खतरनाक चेहरा है। तस्वीर की चोरी अब सिर्फ़ प्रोफ़ाइल फोटो उठाने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी तरह से किसी की पहचान पर हमला बन चुकी है।

तकनीक की इस रफ्तार को रोकना शायद संभव न हो, लेकिन इसके दुरुपयोग को कम करना ज़रूरी है। दुनिया के कई देशों में अब डीपफेक और एआई एडिटिंग पर कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। भारत में भी इस विषय पर चर्चाएं तेज़ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में है और इनके साथ-साथ खतरे भी उतने ही बड़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना इस लड़ाई का सबसे अहम कदम है। जब तक यूज़र यह नहीं समझेंगे कि तस्वीरें कैसे बदली जा सकती हैं और उन्हें पहचानने के तरीके क्या हैं, तब तक वे बार-बार ठगी और भ्रम का शिकार होते रहेंगे। समाधान का दूसरा रास्ता तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारी है। जिस तरह वे नए-नए टूल्स बनाकर लोगों को तस्वीरें बदलने की ताकत दे रही हैं, उसी तरह उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन टूल्स का दुरुपयोग रोका जा सके। उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियां अब तस्वीरों में 'वॉटरमार्क' डालने की कोशिश कर रही हैं, जिससे यह पता चल सके कि कोई फोटो असली है या एआई से बनी हुई। लेकिन यह भी पूर्ण समाधान नहीं है, क्योंकि अपराधी हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं।

फिर सवाल यही है कि इस नकली मुस्कान और नकली चेहरे के दौर में असलीपन को कैसे बचाया जाए? शायद इसका उत्तर संतुलन में छुपा है। तकनीक को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसी तकनीक से चिकित्सा, शिक्षा और कला जैसे क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति भी हो रही है। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना और उसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवार से लेकर सरकार तक और यूज़र से लेकर कंपनियों तक—हर किसी को इस जागरूकता में भागीदारी करनी होगी। तस्वीरें यादों का आईना होती हैं, लेकिन जब वही आईना झूठ दिखाने लगे, तो इंसान के रिश्तों, विश्वास और सच्चाई पर गहरा असर पड़ता है। एआई की ताकत ने यह साबित कर दिया है कि आज मुस्कान भी नकली हो सकती है और चेहरा भी। सवाल सिर्फ़ इतना है कि क्या हम इस नकलीपन को पहचान पाएंगे और असली चेहरे तक पहुंच पाएंगे, या फिर आने वाली पीढ़ियाँ झूठ की दुनिया को ही असलियत मानकर जीने लगेंगी।

भाजपा ने 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान के बजाय चलाया 'दिल्ली में कूड़े को आजादी'- अंकुश नारंग

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली, एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने गुरुवार को करोल बाग जोन के नरायणा वार्ड नंबर 139 में जमा कूड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि दिल्ली को 'कूड़े से आजादी' दिलाएंगे, लेकिन उसने तो कूड़े को ही आजादी दिला दी। दिल्ली की हर सड़क, मैदान, गली में कूड़ा पसरा है और भाजपा सिर्फ सफाई अभियान का दिखावा करने में लगी है।

अंकुश नारंग कहा कि नारायणा से विधायक उमंग बजाज को वार्ड 139 से पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन उनको कूड़े से परेशान लोगों का हाल जानने का भी समय नहीं है। गंदगी के चलते मौसमी बीमारियों का खतरा बरकरार है, लेकिन भाजपा कूड़े को हटाने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान राजेंद्र नगर विधानसभा अध्यक्ष राजन अरोड़ा, देवेंद्र तंवर, वार्ड अध्यक्ष कुलदीप समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

निरीक्षण के दौरान अंकुश नारंग ने बताया कि इस वार्ड से भाजपा के पार्षद उमंग बजाज थे। उमंग बजाज ने पार्षद रहते हुए राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गए। इस विधानसभा और नरायणा की जनता ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें विधायक चुना, लेकिन आज नरायणा वार्ड में उमंग बजाज ने कूड़े का ढेर लगा रखा है।

उन्होंने कहा कि यहां एक तरफ गैस गोदाम है और दूसरी तरफ राजीव गांधी कैंप जाने का रास्ता है। जहां लोग रहते हैं। तीसरी तरफ नरायणा का एकमात्र श्मशान घाट है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, पक्षियों की आवाजें आ रही हैं और मरे हुए जानवर तक यहां मिलते हैं। विधायक बनने

के बाद भी रिक्त पार्षद सीट पर चुनाव नहीं हुआ और यहां इतना कूड़ा जमा है कि लगता है, उमंग बजाज के पास इतना भी समय ही नहीं है कि वह यहां की स्थिति देखने आएं।

उन्होंने कहा कि अभी बरसात और वेक्टर जनित बीमारियों का समय है और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा है। इस गंदगी और कूड़े से अनुमान लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब होंगे। हमने बार-बार नगर निगम की 311 एप पर शिकायत की, लेकिन कोई सुध लेने और देखने को तैयार नहीं है कि यह कूड़ा कैसे हटेगा और लोगों की जिंदगी कैसे आसान होगी।

लाइव टाइम्स एक्सचेंज : मिशन दिल्ली @2047 पर परिवर्तन की दिशा तय

मुख्य संवाददाता

भारत का पहला ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज़ हब लाइव टाइम्स ने 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के ताज पैलेस में अपने प्रमुख सम्मेलन 'लाइव टाइम्स एक्सचेंज' का सफल आयोजन किया। 'मिशन दिल्ली @2047 : भारत की राजधानी का पुनर्निर्माण' थीम पर केंद्रित इस सम्मेलन में देश के प्रभावशाली नेता, नीति निर्माता और चिंतक एक साथ आए और इस बात पर विचार-विमर्श किया कि किस प्रकार भारत की विकास दृष्टि 2047 के अनुरूप दिल्ली को एक वैश्विक और नागरिक-केन्द्रित राजधानी के रूप में बदला जा सकता है।

इस महत्वपूर्ण आयोजन में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद संजय सिंह (आप), सांसद मनोज तिवारी (भाजपा), दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, आशीष सूद, आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता अलका लांबा, दिल्ली के मेयर राजा इक़बाल सिंह, मंत्री परवेश वर्मा, जेएनयू की कुलपति प्रो. संतीश्री धुलीपुड़ी, एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. एम.सी. मिश्रा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मौजूद रहे। इस विविध सहभागिता ने लाइव टाइम्स एक्सचेंज को एक ऐसा अनोखा मंच बना दिया जहां नीतियों, सुशासन और नागरिक कल्याण पर तथ्य-आधारित चर्चा हुई।

लाइव टाइम्स के संस्थापक श्री दिलीप कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा— "लाइव टाइम्स की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि लोग समाचारों से विश्वास खोने लगे थे। 'संपूर्ण सत्य, हर कीमत पर' केवल हमारा नारा नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। एलटी एक्सचेंज ने सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व

और मीडिया तथ्य और जनहित पर मिलकर काम करते हैं, तो लोकतंत्र और भी मजबूत होता है और नागरिक अधिक सशक्त बनते हैं।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुनियादी ढांचे के सुधार पर ज़ोर देते हुए बेहतर सड़कों, सर्वसुलभ जल और सीवर पाइपलाइन, मज़बूत स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ हवा और वास्तविक शिक्षा सुधारों का संकल्प दोहराया। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के पूर्णविद्युतीकरण, सात मिलियन नए पेड़ लगाने और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बहाल करने जैसी घोषणाएँ कीं। उन्होंने कहा— "दिल्ली में बदलाव केवल ढांचों में नहीं बल्कि नीयत में भी दिखाई देगा, और शासन वास्तव में जनता-प्रथम होगा।"

इसी क्रम में मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए 75 सीएम श्री स्कूल स्थापित करने, 21,000 स्मार्ट क्लासरूम पर 900 करोड़ निवेश और क्लीन यमुना मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अपने 30 वर्ष के राजनीतिक अनुभव को साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की विरासत को याद किया और कहा कि नेताओं को स्पष्ट, दीर्घकालिक समाधान लागू करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

सांसद मनोज तिवारी ने अपने निजी संघर्षों और बिहार-यूपी से दिल्ली आए प्रवासियों की कठिनाइयों को साझा किया। उन्होंने गरीबों के लिए 1 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, जीपीएस-युक्त पानी के टैंकर, यमुना की सफाई और यूवीआर-2 सड़क परियोजना जैसी पहलों को गिनाया और कहा— "केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के साथ दिल्ली तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रही है।"

इन चर्चाओं से मिशन दिल्ली @2047 के पाँच स्तंभ स्पष्ट हुए—स्मार्ट और पारदर्शी शासन, सतत हरित बुनियादी ढांचा,

इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित भविष्य परिवहन, ज्ञान और नवाचार का मज़बूत तंत्र, समावेशी विकास जिसमें स्वास्थ्य, आवास और अवसंरचना हर नागरिक तक पहुँचे

सभी नेताओं और विशेषज्ञों ने माना कि नागरिक-केन्द्रित सेवाएँ, डिजिटल सशक्त शासन और पारदर्शी व्यवस्था दिल्ली के पुनर्निर्माण के लिए अनिवार्य हैं।

कार्यक्रम का समापन आशा और संकल्प के साथ हुआ। संदेश साफ था— दिल्ली का भविष्य सहयोग, नवाचार और नागरिक-प्रथम नीतियों पर निर्भर है। लाइव टाइम्स एक्सचेंज ने यह साबित किया कि जब शासन को सत्य और जवाबदेही दिशा देते हैं, तो भारत की राजधानी न केवल खुद को पुनः गढ़ सकती है बल्कि समावेशी शहरी विकास का वैश्विक मानक भी स्थापित कर सकती है।

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा–डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है—
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
● पुराने कपड़े
● पुराने कंबल
● पुराने जूते-चप्पल
● बच्चों के लिए बैग
● किताबें
आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
● दशहरे के दूसरे दिन
● दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
● स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

हरियाणा की ड्रीम पॉलिसी: शिक्षक तबादलों के अधूरे सपनों की हकीकत?

"शिक्षा सुधार का अधूरा सपना या केवल राजनीतिक नारा?"

सरकार ने घोषणा की थी कि इस वर्ष तबादले अप्रैल में होंगे, किंतु सितंबर तक भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। यह देरी न केवल शिक्षकों के साथ वादाख़िलाफ़ी है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई और विद्यालयों के संचालन पर भी सीधा आघात है। हरियाणा सरकार की "ड्रीम पॉलिसी" का उद्देश्य था शिक्षक तबादलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना। शुरुआत में इसे क्रांतिकारी कदम माना गया, लेकिन अब बार-बार शेड्यूल में देरी, तकनीकी पेचीदगियों और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यह विवादों में घिर गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार ने केवल औपचारिकताएँ थोपकर वादाख़िलाफ़ी की है। इसका असर सीधे शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई न हुई तो यह नीति उपलब्धि न बनकर सरकार की विफलता का प्रतीक बन जाएगी।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से कुछ वर्ष पूर्व शिक्षक तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की थी, जिसे बड़े गर्व से "ड्रीम पॉलिसी" का नाम दिया गया। इस नीति को लागू करने का तात्पर्य यह था कि अब शिक्षकों के तबादले केवल वरिष्ठता, मेरिट और प्राथमिकताओं के आधार पर होंगे, न कि सिफ़ारिश या दबाव से। आरंभ में इसे एक क्रांतिकारी कदम माना गया। किंतु बीते वर्षों में इस नीति की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि इस वर्ष तबादले अप्रैल में होंगे, किंतु सितंबर तक भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। यह देरी न केवल शिक्षकों के साथ वादाख़िलाफ़ी है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई और विद्यालयों के संचालन पर भी सीधा आघात है।

शिक्षा केवल विद्यालय भवन या पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर नहीं करती; उसकी वास्तविक धुरी शिक्षक ही हैं। हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में स्पष्ट असमानता है, वहाँ शिक्षकों की उचित तैनाती अत्यंत आवश्यक हो जाती है। ग्रामीण अंचलों के विद्यालय अक्सर योग्य और अनुभवी शिक्षकों से वंचित रहते हैं, जबकि शहरी विद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में शिक्षक तैनात मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में तबादला नीति मात्र प्रशासनिक प्रक्रिया न होकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का एक सशक्त साधन बन जाती है।

सरकार ने दावा किया था कि ड्रीम पॉलिसी से भ्रष्टाचार और पक्षपात का अंत होगा। परंतु, वास्तविकता यह है कि नीति का क्रियान्वयन अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहा है। शिक्षकों को बार-बार एमआईएस अपडेट कराने के निर्देश दिए गए, जिनमें व्यक्तिगत विवरणों से लेकर मोबाइल नंबर तक शामिल रहे। दोहराई जाने वाली इन औपचारिकताओं ने असंतोष को जन्म दिया और तकनीकी त्रुटियों व डेटा की ग़लतियों ने पारदर्शिता के दावे पर प्रश्न खड़े किए। इसके साथ ही सबसे गंभीर शिकायत यह रही कि समय पर ट्रांसफर शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इस देरी के कारण न केवल शिक्षकों के निजी जीवन पर प्रभाव पड़ा, बल्कि विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियाँ भी बाधित हुईं। भले ही प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन बताया गया, परंतु शिक्षकों का आरोप है कि आज भी रसूख़ और सिफ़ारिशों का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

हाल ही में कैथल में हुई बैठक में शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही ट्रांसफर शेड्यूल जारी नहीं किया गया तो सरकार की ड्रीम पॉलिसी स्वयं सरकार के लिए ही बदनामी का कारण बन जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें अनावश्यक औपचारिकताओं में उलझा रखा है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं, किंतु अब तक वादे पूरे नहीं हुए। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखता है। यह असंतोष केवल तबादलों तक सीमित न रहकर सरकार की नीयत और वादाख़िलाफ़ी पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

यदि कोई यह मान ले कि यह विवाद केवल शिक्षकों के हितों तक सीमित है, तो यह गंभीर भूल होगी। अनेक विद्यालय रिक्तियों से जूझते हैं और छात्रों की पढ़ाई प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। बार-बार के विलंब और वादाख़िलाफ़ी से शिक्षकों का मनोबल टूटता है। असंतुष्ट शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित योगदान नहीं दे पाते। जब स्वयं शिक्षक ही नीति पर भरोसा न करें तो समाज और विद्यार्थियों का विश्वास स्वतः डगमगा जाता है।

हरियाणा की राजनीति में शिक्षा सदा ही प्रमुख विषय रही है। सरकारें शिक्षा सुधार के दावे करती रही हैं, किंतु शिक्षक भर्ती, तबादला और पदस्थापन सबसे विवादित मुद्दे बने रहे हैं। ड्रीम पॉलिसी का विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताते हुए जनता के बीच उभारने की तैयारी में है। यदि यह असंतोष बढ़ा तो आगामी चुनावों में यह मुद्दा सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।

सरकार के पास अभी अवसर है कि वह इस नीति को वास्तव में "ड्रीम पॉलिसी" बनाए। इसके लिए ट्रांसफर प्रक्रिया का स्पष्ट कैलेंडर बनाना और उसका पालन करना आवश्यक है। एमआईएस और अन्य ऑनलाइन तंत्र को अधिक सरल व विश्वसनीय बनाना होगा। प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित और मेरिट-आधारित बनाया जाए तथा शिक्षकों के संगठनों से नियमित संवाद स्थापित किया जाए। निर्णय प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, उतना ही विश्वास बहाल होगा।

हरियाणा की ड्रीम पॉलिसी का उद्देश्य प्रशंसनीय था, किंतु इसके क्रियान्वयन में गंभीर कमियाँ सामने आई हैं। यदि सरकार ने इन्हें शीघ्र दूर नहीं किया तो यह नीति सरकार की उपलब्धि न बनकर उसकी विफलता का प्रतीक सिद्ध होगी। शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला है और शिक्षक उसकी नींव। यदि शिक्षक ही असंतुष्ट और उपेक्षित रहेंगे, तो शिक्षा सुधार का सपना अधूरा रह जाएगा। अतः आवश्यक है कि सरकार वादों से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करे, ताकि हरियाणा की ड्रीम पॉलिसी सचमुच "सपनों की नीति" सिद्ध हो सके, न कि केवल एक राजनीतिक नारा।

क्या यही चुनाव आयोग का काम है?

(आलेख : राजेंद्र शर्मा)

बेशक, यह कहना तो शायद बहुत जल्दबाजी होगी कि बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण या एसआइआर की घोषणा के बाद से विपक्षी पार्टियों ही नहीं, बल्कि सामाजिक व जनतांत्रिक अधिकार संगठनों द्वारा भी "वोट की चोरी" के जरिए चुनाव में हेरा-फेरी की जो आशंकाएं जतायी जा रही थीं और जनता के बीच जाकर जतायी जा रही थीं, उनका अंततः निराकरण हो गया है। फिर भी एसआइआर के ही मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 सितंबर के आदेश के बाद, इतना तो निश्चियपूर्वक कहा ही जा सकता है कि इन आशंकाओं के दरवाजे एक हद तक बंद कर दिए गए हैं। यह हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए कि एसआइआर की प्रक्रिया पहचान के लिए प्रमाण के रूप में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जिन 11 दस्तावेजों को अधिसूचित किया गया है, आधार कार्ड / नंबर को उनके समकक्ष, 12वां दस्तावेज माना जाएगा।

सभी जानते हैं कि बिहार में विवादास्पद एसआइआर प्रक्रिया की शुरूआत का एलान करते हुए, चुनाव आयोग ने यह निर्धारित किया था कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के अब तक के सभी उदाहरणों के विपरीत, मताधिकार के सभी दावेदारों को नामांकन फॉर्म भरना होगा और जिनका समुचित नामांकन फार्म निर्धारित तिथि तक अधिकारियों को प्राप्त नहीं होगा, वे खुद-ब-खुद मताधिकार की दावेदारी से बाहर हो जाएंगे। पुनः जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूचियों में नहीं था, उन्हें नामांकन फार्म के साथ अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उक्त 11 साक्ष्यों में से कोई एक पेश करना था। इन साक्ष्यों से आधार, स्वयं चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता पहचान कार्ड और राशन कार्ड जैसे व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने वाले ठीक उन्हीं साक्ष्यों को बाहर रखा गया था, जो सबसे ज्यादा लोगों के पास उपलब्ध हैं और सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं।

हैरानी की बात नहीं है कि विशेष सघन पुनरीक्षण के लिए तय की गयी इस प्रक्रिया विशेष और खासतौर पर उसके लिए सभी मतदाताओं से नये सिरे से फार्म भरवाए जाने और 2003 की मतदाता सूचियों में जिन लोगों का नाम नहीं था, उन सबसे उनकी स्थानीयता को दर्शाने वाले साक्ष्य मांगे जाने और सचेत रूप से आधार समेत सबसे आम-फहम दस्तावेजों के साक्ष्यों की इस सूची से बाहर रखे जाने से, व्यापक रूप से इस कसरत के मकसद को लेकर आशंकाएं पैदा हुई थीं। कहीं यह मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के नाम पर, चोर दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी लाने की यानी मतदाता सूची में स्थान दिए जाने को, नागरिकता की जांच के साथ जोड़ने की कोशिश तो नहीं थी? हमारे संविधान में नागरिकता का विषय, आम तौर पर चुनाव आयोग के विचार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को, नागरिकता जांच के साथ जोड़ना कतई असंवैधानिक है। वास्तव में, बिहार में एसआइआर प्रक्रिया को सर्वोच्च अदालत में दी गयी अनेक चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा, इस प्रक्रिया की संवैधानिकता का है, जिस पर अदालत को अभी विचार करना ही है।

बहरहाल, एसआइआर प्रक्रिया को लेकर विचार की प्रक्रिया में, शुरूआत से ही सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट रुख था कि पहचान के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों में चुनाव आयोग को आधार जैसे दस्तावेजों को शामिल करना चाहिए, जिससे इस प्रक्रिया में लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग भी शुरूआत से आधार आदि दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करने पर अड़ा हुआ था। इन हालात में, जब अदालत आदेश के बजाए, सुझाव की विनम्र भाषा का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग से आधार आदि को शामिल करने की सलाह पर रुक गयी, चुनाव आयोग ने इस सलाह को जैसे अनसुना ही कर दिया। दूसरी ओर, चूंकि अदालत इस संबंध में एकदम स्पष्ट थी कि आधार जैसे दस्तावेजों को अस्वीकार करने की चुनाव आयोग की जिद के पीछे कोई वास्तविक तर्क था ही नहीं, उसने इस प्रकरण की अलग-अलग सुनवाइयों में, कम से कम तीन बार, तरह-तरह से अपने इस मंतव्य को दोहराया कि चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को स्वीकार करे। यहां तक कि एसआइआर की प्रक्रिया में पूरे 65 लाख लोगों के नाम बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से काटे जाने के पहलू पर अपने फैसले में भी अदालत ने, जिन लोगों के नाम इस तरह काटे गए थे, उनकी अर्जियों पर पुनरीक्षण की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर विचार किये जाने का आदेश देते हुए, दस्तावेज के रूप में आधार के स्वीकार किए जाने के स्पष्ट आदेश भी दिये थे।

लेकिन, चुनाव आयोग ने इसके बाद भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने तिकड़मबाजी से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को विफल करने की कोशिशें जारी रखीं। अदालत के उक्त निर्णय की पृष्ठभूमि में, जब चुनाव आयोग की मशीनरी में शामिल कुछ अधिकारियों ने आधार को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की कोशिश की, चुनाव आयोग ने न सिर्फ इसे गलत बताया, बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। और जिन मतदाताओं ने आधार का साक्ष्य के रूप में उपयोग करते हुए, मतदाता सूची में अपना नाम शामिल किए जाने की मांग की, उनके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को नामंजूर ही कर दिया गया। हैरानी की बात नहीं है कि 8 सितंबर की ताजातरीन सुनवाई में अदालत में इन मामलों को उठाया गया और एसआइआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली पार्टियों के वकीलों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना बताते हुए, अदालत से बलपूर्वक आग्रह किया कि आधार के संबंध में अपने मंतव्य का पालन सुनिश्चित करे। ठीक इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट को इस बार अपना स्वर बदलना पड़ा और आधार के संबंध में अपने मंतव्य के लिए, पहले की तरह सुझाव की भाषा का प्रयोग छोड़कर, आदेश की भाषा का प्रयोग करना पड़ा।

जाहिर है कि इसके बाद चुनाव आयोग के पास आधार को अन्य ग्यारह प्रमाणों की तरह, बारहवां प्रमाण मानने से बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है। यानी बिहार के 90-95 फीसदी मतदाता, आधार के सहारे अपनी पहचान तथा पते को प्रमाणित करने की शर्त काफी आसानी से पूरी कर सकते हैं। यह, एसआइआर प्रक्रिया के माध्यम से, मतदाताओं की एक अच्छी-खासी संख्या को मताधिकार से ही वंचित किए जाने की संभावनाओं के दरवाजे, बहुत हद तक बंद कर देता है। याद रहे कि एसआइआर प्रक्रिया के जरिए, मतदाता सूचियों की सत्तानुकूल छंटाई का यह खतरा बहुत ही वास्तविक है। यह संयोग ही नहीं है कि बिहार में, जहां से इस एसआइआर प्रक्रिया की शुरूआत हुई है, एक ओर अगर समूचा विपक्ष इस प्रक्रिया पर, उसके तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने, इस प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर जल्दबाजी में तैयार की गयी कच्ची या ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों तथा त्रुटियों की भरमार पर लागातार सवाल उठा रहा है और इन सवालों को जनता के बीच भी लेकर जा रहा है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी गठजोड़ न सिर्फ इन गड़बड़ियों, त्रुटियों तथा बड़ी संख्या में नाम काटे जाने पर चुप्पी साधे हुए है, बल्कि विशेष रूप से भाजपा तो जोर-शोर से, और आलोचकों पर हमला कर, चुनाव आयोग की तमाम करनियों-अकरनियों का बचाव करने में ही लगी हुई है।

यहां तक कि आरएसएस भी खुलकर विवादास्पद एसआइआर के बचाव में उतर आया है। हाल ही में जोधपुर में संपन्न आरएसएस से संबद्ध संगठनों की तीन दिनी सालाना बैठक के बाद, उसके प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने कहा कि, 'कार्यकुशल चुनावी प्रक्रियाएं जनतंत्र की रीढ़ होती हैं और एसआइआर जैसी पहलें इस आधार को मजबूत करने में मदद करती हैं।' सचाई यह है कि बढ़ती "बाहरी" घुसपैठ की जिस तरह की निराधार आशंकाओं तथा डैमोग्राफी में बदलाव की चिंताओं को, मोहन भागवत के पिछले ही दिनों के तीन दिवसीय महत्वाकांक्षी व्याख्यान में स्वर दिया गया था और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उछाला गया था, उन्हें ही और पहले से स्वर देते हुए, एसआइआर प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने को, रोहिंगिया, बंगलादेशी घुसपैठियों आदि की मौजूदगी का संकेतक बताने की कोशिश की जा रही थी। यह सब चुनाव आयोग के नाम पर, कथित सूत्रों के हवाले से किया जा रहा था। यह दूसरी बात है कि सूत्रों और इशारों में धारणाएं बनाने का यह खेल शुरू करने के बाद, नाम काटे जाने के औपचारिक कारण के स्तर पर, चुनाव आयोग ऐसे दावों से पीछे ही हट गया।

नरेंद्र मोदी के निजाम में वैसे तो तमाम संवैधानिक निकायों, संस्थाओं तथा एजेंसियों को घसीटकर, उनकी मान्य भूमिकाओं से काफी दूर पहुंचा दिया गया है। पर चुनाव आयोग, संविधान में सौंपी गयी अपनी भूमिका से जितनी दूर चला गया है, वह हैरान कर देने वाला है। जो चुनाव आयोग बड़ी संख्या में हाशियावर्ती मतदाताओं की छंटाई के अपने आग्रह को पूरा करने के लिए, आधार को पहचान का साक्ष्य मानने से इंकार करने पर आखिर-आखिर तक बजिद था, उसी चुनाव आयोग के बंगलूरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभाई क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा वोटों की हेराफेरी के आरोपों पर मुंह सिलकर बैठ जाने के बाद, अब उसी कर्नाटक में अलंद विधानसभाई क्षेत्र में, 2023 के विधानसभाई चुनाव से पहले लगभग 6 हजार मतदाताओं के नाम फर्जीवाड़े के जरिए कटवाए जाने के दोषियों की सीआइडी जांच, चुनाव आयोग द्वारा पुलिस द्वारा मांगा गया डॉटा न देने के जरिए, दो साल से रोक कर रखे जाने का मामला सामने आया है। क्या यही चुनाव आयोग का काम है?

14 सितम्बर हिन्दी दिवस पर विशेष : विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है हिन्दी

रमेश सर्राफ धमोरा

हिन्दी एक भारतीय इंडो-यूरोपीय भाषा है जो संस्कृत से विकसित हुई और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में ही संस्कृत, मराठी, नेपाली और कई अन्य भारतीय भाषाएँ भी लिखी जाती हैं। देवनागरी का अर्थ है ₹देवताओं की लिपि₹ या ₹शहर की लिपि₹। यह संस्कृत के दो शब्दों 'देव' (ईश्वर/देवता) और 'नागरी' (नगर/शहर से लिया गया विशेषण) से मिलकर बना है। देवनागरी एक ब्राह्मी-आधारित वर्णमाला है जिसका उपयोग भारत की कई भाषाएँ जैसे हिंदी, मराठी और संस्कृत को लिखने के लिए किया जाता है। इसीलिए हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की प्रत्यक्ष वंशज कहा जाता है।

हिंदी भाषा एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत आसान और सरल माध्यम प्रदान करती है। यह प्रेम, मिलन और सौहार्द की भाषा है। हिन्दी विविध भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत में समझा जाता हो। उस भाषा के प्रति आज भी इतनी उपेक्षा व अवज्ञा क्यों ? प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिन्दी भाषा को आसानी से बोल-समझ लेता है। इसलिए इसे सामान्य जनता की भाषा अर्थात जनभाषा कहा गया है।

हिन्दी भारत सरकार की आधिकारिक भाषा है और हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। हिंदी भाषा का अर्थ है ₹भारत या हिंद से संबंधित₹। यह भारत की आधिकारिक राजभाषा है और दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसका इतिहास प्राचीन संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से जुड़ा है। हिन्दी भाषा का जन्म भारत में ही हुआ था। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है। बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारतेन्दु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। जिन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया था।

भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है जो हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले सौ सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। भारत में धर्म, परंपराओं और भाषा में विविधता के बावजूद यहां के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। इसीलिए हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिन्दी के ज्यादातर शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। यह मुख्य रूप से आर्यों और पारसियों की देन है। इस कारण हिन्दी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। जहां अंग्रेजी में मात्र 10 हजार मूल शब्द हैं। वहीं हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या 2 लाख 50 हजार से भी अधिक है। हिन्दी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ हमारी राजभाषा भी है।

हिन्दी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और दिल्ली राज्यों की राजभाषा भी है। राजभाषा बनने के बाद हिन्दी ने विभिन्न राज्यों के कामकाज में लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का अभिनव कार्य किया है। लेकिन विश्व भाषा बनने के लिए हिन्दी को अब भी संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों के दो तिहाई देशों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। हम संभावनाएं जता सकते हैं कि शीघ्र ही हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान अधिकतर अपना सम्बोधन हिन्दी भाषा में ही देते हैं। जिससे हिन्दी भाषा का महत्व विदेशी धरती पर भी बढ़ने लगा है।

हिन्दी ने भाषा, व्याकरण, साहित्य, कला, संगीत के सभी माध्यमों में अपनी उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं वर्चस्व कायम किया है। हिन्दी की यह स्थिति हिन्दी भाषियों और हिन्दी समाज की देन है। लेकिन हिन्दी भाषा समाज का एक तबका हिन्दी की दुर्गति के लिए भी जिम्मेदार है। अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी होता है। यह धारणा हिन्दी भाषियों में हीन भावना लाती है। जिंदगी में सफलता पाने के लिये हर कोई अंग्रेजी भाषा को बोलना और सीखना चाहता है। हिन्दी भाषी लोगों को इस हीन भावना से उबरना होगा, क्योंकि मौलिक विचार मातृभाषा में ही आते हैं। शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा विचार करना सिखाती है और मौलिक विचार उसी भाषा में हो सकता है जिस भाषा में आदमी जीता है। हमें अहसास होना चाहिये कि हिन्दी दुनिया की किसी भी भाषा से कमजोर नहीं है।

अंग्रेजी व चीनी भाषा मंदारिन के बाद हिन्दी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। नेपाल, पाकिस्तान की तो अधिकांश आबादी को हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना आता है। बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान में भी लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। फिजी, सुरिनाम, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे देश की सरकारें तो हिंदी भाषियों द्वारा ही चलायी जा रही हैं। पूरी दुनिया में हिंदी भाषियों की संख्या करीबन एक सौ करोड़ से अधिक है।

आदिकाल से अब तक हिन्दी के आचार्यों, सन्तों, कवियों, विद्वानों, लेखकों एवं हिन्दी-प्रेमियों ने अपने ग्रन्थों, रचनाओं से हिन्दी को समृध्द किया है। परन्तु हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने विचारों, भावों एवं मतों को विविध विधाओं के माध्यम से हिन्दी में अभिव्यक्त करें एवं इसकी समृध्दि में अपना योगदान दें। कोई भी भाषा तब और भी समृध्द मानी जाती है जब उसका साहित्य भी समृध्द हो। बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का अन्तरराष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे-बड़े केन्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध के स्तर तक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से हिन्दी में दर्जनों पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं। हिन्दी भाषा और इसमें निहित भारत की सांस्कृतिक धरोहर सुदृढ और समृद्ध है। इसके विकास की गति बहुत तेज है।

देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के एक साथ विकास के कारण हिन्दी ने कहीं ना कहीं अपना महत्ता खो दी है। आज हिन्दी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा है। बहुत से बड़े समाचार पत्रों में भी अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी का उपयोग किया जाने लगा है। जो हिन्दी भाषा के लिये शुभ संकेत नहीं हैं। रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। जहां सॉफ्टवेयर की मदद से रूपांतर कर अंग्रेजी से हिन्दी भाषा बनायी जाती है। जिसमें ना मात्रा का ख्याल रहता है और ना ही शुद्ध वर्तनी का। वर्तमान समय में हिन्दी भाषा के समाचार पत्र पत्रिकायें धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं।

हिन्दी दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिये के हम पूरे मनोयोग से हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में अपना निस्वार्थ सहयोग प्रदान कर हिन्दी भाषा के बल पर भारत को फिर से विश्व गुरु बनवाने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। अब तो कम्प्यूटर पर भी हिन्दी भाषा में सब काम होने लगे हैं। कम्प्यूटर पर हिन्दी भाषा के अनेकों सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से कार्य कर सकते हैं।

बदायूं जिला न्यायालय परिसर के कंप्यूटर विभाग का पैसे के लेनदेन के साथ वीडियो वायरल

मामला उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का है। जहां कंप्यूटर विभाग ,जनपद न्यायालय परिसर बदायूं यूपी की खिड़की है जहां खुलेआम रिश्वत लेकर पत्रावली ली जाती हैं। समय पर पेश करने पर सामान्य 100 या 50 रुपए का शुल्क है। विलंब शुल्क 200 से 500 रुपए तक है।

अखिलेश दुबे गिरोह का दमन : यदा - यदा हि धर्मस्य, मतलब आई पी एस अखिल कुमार

सुनील बाजपेई

कानपुर। ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के और भी प्रांतों में चर्चा का विषय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से जुड़े लोगों की वजह से देश के एकमात्र पहले बहुत प्रभावशाली सफेदपोश अखिलेश दुबे और उनके गिरोह के खिलाफ लगातार मिल रही पीड़ितों की शिकायतों पर सभी आवश्यक कारवाइयां लगातार जारी हैं।

याद रहे कि भारत का यह पहला ऐसा खतरनाक चालाक गिरोह है , जिसने अपनी सफलता का आधार एन केन प्रकारेण सिपाहियों से लेकर पीपीएस और आई पी एस अधिकारियों ,पत्रकारों ,नेताओं और वकीलों के सहयोग को बना रखा था और उनके सहयोग से ही विष कन्याओं के माध्यम से लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर ब्लैकमेलिंग जमीनों, मकानों और भूखंडों पर जबरन कब्जे जैसा अपना हर इरादा पूरा कर रहा था।

अब बात कानपुर की पुलिस कमिश्नर के रूप में सरगना अखिलेश दुबे और उसके गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अखिल कुमार की। जिनकी अथाह निडरता, जिनकी ईमानदारी और जिनकी कर्तव्य के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा ही अखिलेश गिरोह का भंडाफोड़ करने का कारण बनी। इस हिसाब से जुझारू अखिल कुमार अखिलेश, अवनीश और वकील दीनू उपाध्याय जैसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले देश के पहले आईपीएस है ,जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अखिलेश दुबे गिरोह ,क्योंकि देश में अखिलेश जैसा ऐसा गिरोह पहली बार ही प्रकाश में आया है ,जिसमें लोकतंत्र के चारों खंभे पुलिस ,पत्रकार ,वकील और नेता भी शामिल है। इसीलिए सरगना अखिलेश को जेल भेजना और उसके गिरोह का भंडाफोड़ करना आदमखोर शेर की माद में हाथ डालने से भी ज्यादा खतरनाक था। केवल वही नहीं,

उसके साथ और भी कई आदमखोर। वह भी साधारण नहीं। असाधारण। सरगना अखिलेश से लाभ उठाने के मामले में केवल भ्रष्ट नहीं महाभ्रष्ट, जिनकी अखिल कुमार के खिलाफ साजिशें भी बदले के इरादे से लगातार जारी बताई जातीं है। जिसमें मुख्य भूमिका उन पुलिस अधिकारियों की होने का दावा सूत्रों ने किया है , जिनके महा भ्रष्ट स्वार्थी चेहरे भी अखिलेश गिरोह के साथ बेनकाब हुए हैं। मतलब बदला लेने के इरादे से यह सभी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि जिन्हें परमेश्वर अपना माध्यम बनाता है। अखिलेश जैसा उनका बाल बांका कभी नहीं कर पाता है। क्योंकि जब अखिलेश, अवनीश या दीनू जैसे किसी के भी पाप का घड़ा भर जाता है ,तो उसे फोड़ने के लिए खुद परमेश्वर ही योगी आदित्यनाथ और आईपीएस अखिल कुमार बन जाता है। वही परमेश्वर इसके लिए क्रम बद्ध रास्ता भी बनाता है। जिसका एस एस पी की जगह पुलिस कमिश्नरेट के गठन से भी नाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या कोई एस एस पी पदधारक ऐसा कर पाता ?

इसी क्रम में जब उचित समय आया, तभी कानपुर ने अखिल कुमार के रूप में एक तरह से परमेश्वर को ही पाया। इसकी पुष्टि रामचरितमानस में जब जब होइ धरम कै हानी, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहिं दयानिधि सज्जन पीरा।" और श्रीमद्भगवद्गीता में भी "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत" लिख कर भी की गई है।

चूंकि जनहित के मामले में हर दृष्टिकोण से संपूर्ण यानी अखिल निडरता, अखिल ईमानदारी , अखिल कर्तव्यनिष्ठा , अखिल पीड़ित हित ,अखिल परोपकार और सहायता का ईश्वर ,अल्लाह और गॉड से ही नाता है। यही वजह है कि हर संभव कोशिश के बाद भी आई पी एस अखिल को कोई खरीद या डरा नहीं पाता है। और उन्हीं की निडरता पूर्ण विशुद्ध ईमानदारी का शक्ति चक्र अखिलेश जैसे देश व्यापी गिरोह के असम्भव जैसे चक्रव्यूह का भेदन सम्भव कर दिखाता है।

एक और बात के लिए भी आईपीएस अखिल कुमार की विशुद्ध ईमानदारी सराहना की सीमाएं तोड़ने वाली है ,जिसका संबंध पुलिस थानों की नीलामी से है। मतलब काफी अरसे बाद आईपीएस अखिल कुमार के रूप में ऐसा ईमानदार पुलिस अधिकारी मिला, जिसने रिश्वत के बल पर थानों के चार्ज हासिल करने के हर इरादे पर पानी फेर दिया। जबकि पूर्व में बहुत से ऐसे भी कई भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी रहे जो पुलिस थानों की नीलामी के बदले लाखों करोड़ों रुपया पैदा कर ले जाने में भी सफल रहे। इसके लिए उन्होंने अपना मुख्य माध्यम इसी अखिलेश दुबे को बना रखा था।

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में निर्भीकता और ईमानदारी की सीमाएं तोड़ने वाले आईपीएस अखिल कुमार के आलावा कोई और प्रभावशाली सफेद पोस माफिया अखिलेश दुबे का असली चेहरा बेनकाब ही नहीं कर सकता था। मतलब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं होता और अखिल कुमार जैसा निर्भीक और ईमानदार आईपीएस नहीं होता तो फिर अखिलेश दुबे जैसे गिरोह का भंडाफोड़ कभी नहीं होता।

संविधान और कानून के तहत हिंदी की विकास गाथा लिखी जा रही...

हिंदी भाषा के निरंतर विकास की गाथा नीति निरंतर लिखीं जा रही है । यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है ।निरंतर हिंदी भाषा को उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है । जो हमारी भाषा की उन्नति में मददगार सिद्ध हो रही है । हिंदी भाषा की और कितनी आने वाले समय में प्रगति होगी इसको मापन आसान नहीं होगा । हर क्षेत्र में संस्था , दाल , समूह इस और विशेष रूप से ध्यान दे रही है यह एक प्रगति वादी सोच ही हिंदी को बढ़ाने से सतत्प्रयत्नशील है। अन्य भाषाओं के तथाकथित नेताओं की स्वार्थ गत नीतियों के चलते हिंदी भाषा का आज हर तरफ विरोध करने पर उतारू है यह वर्तमान समय में देखने को आ रहा है ।

संविधान और कानून की सशक्त अभिव्यक्ति का मतलब क्या है ? यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कानून की सशक्त अभिव्यक्ति का मतलब यही है कि , संविधान और कानून आमजन की आवाज को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और उनकी रक्षा करने का एक साधन होना चाहिए। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, और न्याय तक पहुंच जैसे कई अधिकार , दायित्व , कर्तव्य शामिल हैं। जहां न्याय सत्यता की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना यह सब तभी संभव है जब हमारी हिंदी भाषा को सशक्त रूप से पूर्ण ईमानदारी के साथ संविधान और कानून की भाषा में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाए । विगत कुछ वर्षों में संविधानकी भाषा एवं कानूनी भाषा में हिंदी का बढ़-चढ़कर प्रयोग किया जा रहा है यह स्वीकार योग्य कदम है । संविधान और कानून की सशक्त अभिव्यक्ति हिंदी भाषा के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएं तो वह हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ही मातृभाषा की अभिव्यक्ति है । मातृभाषा हिंदी का प्रयोग देश का प्रत्येक नागरिक बिना किसी डर के या फिर किसी प्रतिबंध के अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है । इसमें व्यक्ति अपने विचारों को मौलिक अथवा लिखित रूप में भी कर सकता है । बता सकता है । दिखा सकता है । हिंदी भाषा को उपयोग जाति धर्म या कोई भी विशेष वर्ग का ही क्यों ना हो वह कहीं ना कहीं अपने हिंदी भाषा को उपयोग आजकल और भविष्य में भी आता रहेगा ।

जिस तरह से देश के सभी नागरिकों को न्याय पाने का एक सुनिश्चित अधिकार , दायित्व और कर्तव्य संविधान द्वारा दिया गया है कई अधिकार तो हमें मालूम है और वह कानून के माध्यम से इसका उपयोग करता है इसके पीछे हमारी मातृभाषा का ही प्रभाव है जो संविधान के साथ कानून पर भी अपना अधिकार रखती है। जिससे संविधान की भाषा और कानून की तमाम प्रकार की धाराओं को अपनी भाषा में समझाने का सहज वह सरल तरीका हिंदी भाषा ही है । जिससे आम नागरिकों को न्याय जल्दी मिल जाता है । सभी नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए , और कानूनी सहायता और प्रक्रियाएं सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए । संविधान और कानून की सशक्त अभिव्यक्ति हिंदी भाषा एक मजबूत और न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है । यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि , संविधान और कानून नागरिकों की आवाज को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और उनकी रक्षा करने का एक साधन है । यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को बिना किसी डर या प्रतिबंध के अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। इसमें विचारों, सूचनाओं और राय को व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है, चाहे वह मौखिक, लिखित, या किसी अन्य रूप में हो । हिंदी भाषा देश की सर्वोत्तम ज्ञानपीठ भाषा है यह आम नागरिकों के बीच अपना तक के भाव वाले स्वभाव को परिभाषित करती है । यह विचारों की संरचना के साथ कल्पना की तमाम शक्तियों और बोलने , लिखने , कहने का अधिकारों के साथ कई दायित्वों के चलते हिंदी अब और अधिक सुदृढ़ बनती जा रही है ।

अंत मैं यही कहना चाहता हूं कि , यह सच है कि जीवन में प्रगति के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करने से हमें सफलता मिलती है और इसका महत्व बढ़ाया जा रहा है यह ऊर्जा से भरी हुई हमारी सोच है ।

प्रकाश हेमावत

वृन्दावन शोध संस्थान द्वारा प्रियाबल्लभ कुंज में हुआ साँझी संवाद का आयोजन

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। वृन्दावन शोध संस्थान द्वारा आयोजित साँझी महोत्सव-2025 के पांचवें दिन छीपी गली/पुराना बजाजा स्थित ठाकुर श्रीप्रियावल्लभ कुंज में साँझी संवाद का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ ।जिसके अंतर्गत 'साँझी रचना एवं साँझी का ब्रजभाषा साहित्य और कला यात्रा' विषयक संगोष्ठी, पुष्प एवं जल साँझी रचना, पद गायन तथा साँझी साहित्य पर आधारित प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए।

संगोष्ठी में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के संस्थापक पण्डित चंद्रलाल शर्मा ने कहा कि ब्रज की साँझी परंपरा मंदिर तथा गांवों में बनने वाली साँझी दोनों धरातलों पर अपनी विशेषता की अभिव्यक्ति करती है। कलागत सौन्दर्य के साथ ही साँझी परंपरा से जुड़ा साहित्य और संगीत इसकी विशेषता को दर्शाता है।

ठा. श्रीप्रियावल्लभ कुंज के सेवायत आचार्य विष्णुमोहन नागार्च ने कहा कि साँझी के घरानों में श्रीप्रियावल्लभ कुंज का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ श्रीहित परमानंददास महाराज ने ब्रजभाषा में साँझी के विपुल पदों की रचना की है ।श्रीहित परमानंददास महाराज के द्वारा रचित साँझी साहित्य का प्रमाण प्राचीन पाण्डुलिपियों में देखने को मिलता है।

ब्रज साहित्य सेवा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि वृन्दावन शोध संस्थान के द्वारा पितृ पक्ष में सांझी संवाद के जो आयोजन प्रतिदिन विभिन्न देवालयों में किए जा रहे हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि संस्थान के इस कार्य से न केवल लुप्त प्राय सांझी कला का विस्तार होगा अपितु ब्रज संस्कृति भी संरक्षित और संवर्धित होगी।

प्रमुख शिक्षाविद् डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा ने कहा कि साँझी ब्रज का महत्वपूर्ण उत्सव है। यह पितृ पक्ष के सोलह दिनों तक लोक एवं देवालयों में मनाया जाता है। साँझी लीला को रसिक भक्तों ने प्रचुरता से गाया है।

प्रिया वल्लभ मंदिर के अंग सेवी एवं सांझी के जाने-माने चित्रकार आचार्य रसिक वल्लभ नागार्च ने कहा कि वृन्दावन शोध संस्थान के प्रयासों से लोगों में साँझी के प्रति जागरूकता पुनः फैल रही है। इसके लिए संस्थान बधाई का पात्र है।

साथ ही उन्होंने श्रीहित परमानंददास महाराज के द्वारा रचित साँझी पद का गायन किया गया।

आचार्य विभुकृष्ण भट्ट ने कहा साँझी में साहित्य के साथ ही इसके कला पक्ष एवं संगीत की समृद्ध परंपरा रही है।

इस अवसर पर श्रीप्रियाबल्लभ कुंज में फूलों की साँझी एवं जल साँझी का प्रस्तुतिकरण विराटनारायण शर्मा तथा सार्थक शर्मा द्वारा किया गया।

संगोष्ठी में आचार्य अंबरीश भट्ट, सुमनकांत पालीवाल, रामनारायण शर्मा ब्रजवासी, योगेश योगीराज, विष्णुकांत शर्मा, आचार्य सतीश गोस्वामी एडवोकेट, गोविन्दनारायण शर्मा, ब्रजेश शर्मा, गोविन्द शरण पचौरी, गौरीशंकर शर्मा, डॉ.राधाकांत शर्मा, मनमोहन शर्मा, मुकेश शर्मा, जितेन्द्र शर्मा, मुकेश शर्मा, शशिकांत चौबे, रामलाल ब्रजवासी, मदनमोहन, उमाशंकर पुरोहित, श्रीजी सरांठे, दिशा सरांठे एवं सुजाता सरांठे आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए ।संचालन डॉ. राजेश शर्मा ने किया ।संगोष्ठी का समापन स्वल्पाहार के साथ हुआ।

ट्रंप के लाडले का मर्डर क्यों ? -दुनियाँ के सामने सबसे बड़ा सवाल ?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर नेपाल में जेन जी आंदोलन अभी थमा ही नहीं है बल्कि उनमें ही आपसी फूट के नज़ारे दिख रहे हैं उधर फ्रांस में जेन जी के लिए सोशल मीडिया पर बैन की खबर पर चर्चा जारी है,लेकिनअमेरिका में अपने विचारों से जेन जी पर असर डालने वाले कंजरवेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त चार्ली कर्क की हत्या, पूरी दुनियाँ के लिए इससे भी बड़ी खबर बनी हुई है, अमेरिका,यूरोप और दुनियाँ भर के मुस्लिम मुल्कों के साथ साथ भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या पर चर्चा की जा रही है,सिर्फ 31 साल के चार्ली कर्क अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कितने महत्वपूर्ण थे,उसे इस तरह समझा जा सकता है,उनकी हत्या के बाद ट्रंप ने अमेरिकी झंडे को चार दिन तक झुका कर रखने का आदेश दिया है, इसी के साथ ट्रंप ने कर्क के हत्यारे को किसी भी कीमत पर पकड़कर सजा देने का भी एलान किया है। चार्ली कर्क की उस वक्त गोली मारकर हत्या की गई जब वो अमेरिका की यूटायूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत कर रहे थे, अचानक एक गोली चली जो उनके गले में लगी,अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि,दुनियाँ के सामने सबसे बड़ा सवाल है चार्ली कर्क को किसने मारा ?उसकी हत्या क्यों की गई, क्या यह हत्या अमेरिका में एक बहुत बड़े विभाजन का अलॉर्म बजा रही है ? क्या चार्ली कर्क को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक थे ?चार्ली की हत्या उस वक्त की गई जब वो कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं यानि जेन ज़ी के बीच ट्रंप की विचारधारा को बढ़ाने के अभियान पर निकले थे।चूँकि ट्रंप के`लाडले` का मर्डर क्यों ?दुनियाँ के सामने सबसे बड़ा सवाल?, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,राजनीतिक मतभेद अब सिर्फ भाषणों या विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं,बल्कि हिंसा का रूप ले रहे हैं ?-चार्ली की हत्या एक गंभीर संकेत है।

साथियों बात अगर हम हत्या की टाइमिंग की करें तोसिर्फ 31साल के चार्ली अमेरिकन कमबैक टूर पर थे,इस कार्यक्रम का आयोजन चार्ली के संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए ने किया था,इस संगठन की स्थापना चार्ली ने सिर्फ 18 साल की उम्र में की थी,इस छात्र संगठन का मकसद अमेरिकी कॉलेजों में कंजर्वेटिव विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना है, कंजर्वेटिव विचारधारा ये मान्यता रखती है कि पुरानी परंपराएं, धर्म, रीति-रिवाज़ और नैतिक मूल्य समाज को स्थिर और मजबूत बनाते हैं, यानि ये पुराने रीति रिवाजों के बदलाव का विरोध करती है। इसके अलावा राष्ट्र की संप्रभुता, झंडा, सेना और राष्ट्रीय पहचान के प्रति गर्व और निष्ठा की भावना रखती है,यानि ये अमेरिकी की राष्ट्रवादी विचारधारा है,अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इसी विचारधारा को फॉलो करती है। इसी वजह से चार्ली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी थे, और विरोधियों के निशाने पर रहते थे ।अपने अमेरिकन कमबैक टूर पर वह कैंपस में युवाओं से संवाद करने वाले थे, यूटा वैली यूनिवर्सिटी उनका पहला स्टाप था, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई ।हम कह सकते हैं चार्ली की हत्या उस वक्त की गई जब वो कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं यानि जेन ज़ी के बीच ट्रंप की विचारधारा को बढ़ाने के अभियान पर निकले थे।

साथियों बात अगर हम चार्ली कर्क के दृष्टिकोणों को समझने की करें तो (1)गर्भपात-: उन्होंने एबॉर्शन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, और कुछ बयानों में यह बताया गया कि यदि 10 वर्षीय लड़की के साथ यौन शोषण हो और गर्भधारण झाल, तो क्या किया जाए, इस तरह के सवालों पर उनके दृष्टिकोण कण्ट्रोवरसी पैदा कर चुके हैं।(2) गन राइट्सः-बंदूक-स्वामित्व, आत्मरक्षा,उन्होंने गन राइट्स को समर्थन दिया।(3) राष्ट्रवाद, सदैव "अमेरिका फर्स्ट "जैसी विचारधारा : उनके भाषणों में अमरीकी संप्रभुता, सीमाएँ, आव्रजन (इमाइग्रेशन) आदि मुद्दों पर कठोर दृष्टिकोण देखा जाता है। (4)लेफ्ट विरोधःउन्होंने लेफ्ट-लिबरल और

प्रोग्रेसिव समूहों की आलोचना की है, विशेष तौर पर कॉलेज परिसरों में फ्री स्पीच,वोके कल्चर, डाइवर्सिटी, इन्क्लूशन आदि मुद्दों पर। यह दायरा अक्सर ट्रंप समर्थकों और दक्षिणपंथी विचार प्रकारों में मौजूद है ।इस तरह, उनके विचार उन्हें ट्रंप समर्थक और लेफ्ट-विरोधी बनाते थे।

साथियों बात अगर हम हत्या और राजनीतिक हिंसा की करें तो पहले भी राजनीतिक हिंसा और हत्या हुई है, उदाहरण के लिए, सांसदों, एक्टिविस्टों, प्रदर्शनकारियों पर हमले, गोलियाँ चलना आदि। लेकिन यह कहना कि हर मुखर समर्थक या हर "विचारधारा के व्यक्ति" ख़तरे में है, सही नहीं होगा ।चार्ली की हत्या एक गंभीर संकेत है कि राजनीतिक मतभेद अब सिर्फ भाषणों या विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हिंसा का रूप ले रहे हैं। यह घटना "पॉलिटिकल असासिनेशन" कहलायी है ।नया नहीं, मगर बढ़ती प्रवृत्तिः-ऐसी घटनाएँ नई नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में पोलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस में वृद्धि देखी गई है। चार्ली कुर्क की हत्या इस प्रवृत्ति का एक और दुखद उदाहरण है।

साथियों बात अगर हम क्या चार्ली कुर्क की हत्या यह ट्रंप के लिए भारी पड़ेगी-संभवतः हाँ, निम्न कारणों सेः (1) राजनीतिक संवाद और हिंसा की आलोचनाः ऐसी हत्या राजनीतिक हिंसा के प्रश्न को देशव्यापी बना देगी। ट्रंप, जो अक्सर "लेफ्ट -विंग एक्स्ट्रामिस्म" या "रेडिकल लेफ्ट रहेटोरिक" की बात करते हैं, उन्हें इस घटना में अपनी आलोचना का केंद्र बनना पड़ेगा। (2)न्याय और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारीः प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि कानून-व्यवस्था कायम हो; यदि हो कि हत्या की जांच में देरी हो,साजिश या राजनीतिक गलत दावों से स्थिति बिगड़े, तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है।(3) मतदाता भावना पर असरः उनके समर्थकों में दुःख और गुस्सा होगा; विपक्ष इस घटना का इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ उठा सकता है, "हिंसात्मक राजनीति" की आलोचना करते हुए।(4)मीडिया और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाः अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव है, यूरोप के दक्षिणपंथी नेता आदि, मीडिया, मानवाधिकार संगठन इसकी समीक्षा कर रहे हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पुरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप के लाडले का मर्डर क्यों ?दुनियाँ के सामने सबसे बड़ा सवाल ?राजनीतिक मतभेद अब सिर्फ भाषणों या विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं,बल्कि हिंसा का रूप ले रहे हैं ?-चार्ली की हत्या एक गंभीर संकेत है,वक्तव्य देते समय वक्ताओं, मीडिया, नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि भाषा संयमित हो, उत्तेजना कम हो, लेकिन सक्रिय आलोचनाएँ हों,यह लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।

मोदी सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन

शमशेर खरक

जीएसटी की दरों में हालिया बदलाव ने छोटे उद्योगों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। 2025 में कई सामानों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। मिसाल के तौर पर, 28 प्रतिशत के स्लैब से कई उत्पादों को 18 प्रतिशत और कुछ को 12 से 5 प्रतिशत तक लाया गया है।

कोई भी देश तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, जब वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खुद बनाए। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना इस दिशा में सबसे जरूरी कदम है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश अपने छोटे और कुटीर उद्योगों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। देश की समृद्धि तभी संभव है, जब आयात और निर्यात का संतुलन बना रहे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। आज वैश्विक दबावों के बीच भारत में स्वदेशी को बढ़ाने की बात जोर-शोर से हो रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है जीएसटी की दरों में कटौती। उनका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और जीएसटी में राहत छोटे उद्योगों को सस्ता कच्चा माल और कम लागत देकर इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मोदी सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भी है। जब देशवासी स्थानीय उत्पादों को अपनाते हैं, तो वे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने इतिहास, कारीगरी और परंपराओं को भी संजोते हैं। आज, भारतीय उपभोक्ता पहले से अधिक सजग हैं। वे समझते हैं कि हर स्वदेशी खरीदारी एक रोजगार का सृजन करती है और एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करती है।

घरेलू उद्योगों को एक पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी भारत का सपना अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के बाद अब सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दी जा रही राहतों के जरिए घरेलू उद्योगों को एक नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ आवश्यक घरेलू उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की गई है। इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम दर्जे के स्वदेशी निमार्ताओं को मिलेगा। इससे न केवल उनकी उत्पादन लागत घटेगी, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, हैंडलूम वस्त्र, बांस उत्पाद, घरेलू खिलौने और आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी दरों में राहत दी गई है, जो ग्रामीण भारत और पारंपरिक उद्योगों को एक नई ऊर्जा देगी।

छोटे कारोबारियों को फायदा

जीएसटी की दरों में हालिया बदलाव ने छोटे उद्योगों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। 2025 में कई सामानों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। मिसाल के तौर पर, 28 प्रतिशत के स्लैब से कई उत्पादों को 18 प्रतिशत और कुछ को 12 से 5 प्रतिशत तक लाया गया है। इससे उत्पादन की लागत कम होगी, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर-फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में, जहां जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि छोटे कारोबारियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा, उनकी लागत 7-8 प्रतिशत तक कम होगी, और वे बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इस कदम से न सिर्फ उत्पादन सस्ता होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी और अन्य सामानों पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत होने से उनकी कीमतें 7-8 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, खासकर ऑटो, कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में। नतीजतन, छोटे उद्योगों की के सामान की बिक्री बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वैश्विक बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेंगी

जीएसटी में कटौती का एक और बड़ा फायदा निर्यात के क्षेत्र में दिखेगा। कम टैक्स से भारतीय उत्पादों की कीमतें वैश्विक बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेंगी। खासकर लेदर और फुटवेयर जैसे निर्यात-आधारित उद्योगों को इससे खासा लाभ होगा। ये क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, और इनकी मजबूती से ग्रामीण और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स जैसे क्षेत्रों में कारीगरों को सस्ता कच्चा माल और बेहतर मुनाफा मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका सुधरेगी।

वोकल फॉर लोकल का नारा

भारत विविधताओं वाला देश है, जहां हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, कारीगरी, उत्पाद और संस्कृति है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण हमारे देश के लोकल उत्पादों की उपेक्षा होती रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो आत्मनिर्भर भारत की नींव रखता है वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्थानीय उत्पादों के लिए आवाज उठाना और उनका समर्थन करना। इसका उद्देश्य है कि हम देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता दें, उन्हें अपनाएं, और उनके प्रचार-प्रसार में मदद करें ताकि स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिले।

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

विदेशी उत्पादों पर निर्भरता को कम कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाना भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। जब हम स्थानीय उत्पादों को खरीदते हैं, तो इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हमारे देश की हस्तकला, कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, और अन्य पारंपरिक उत्पादों को समर्थन मिलता है। देश में ही उत्पादन और खपत से पैसे का प्रवाह देश के भीतर रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

आम जनता की भूमिका रहे

हमें विदेशी ब्रांड्स के पीछे भागने की बजाय भारतीय उत्पादों को अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोकल उत्पादों का प्रचार करना चाहिए। त्योहारों और अन्य अवसरों पर भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए सामान का उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर आज खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे पतंजलि आदि को अपनाकर लोग वोकल फॉर लोकल को समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी, कश्मीर का कढ़ाईदार वस्त्र, और राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं सब हमारी लोकल ताकतें हैं।

गेम-चेंजर साबित होगा फैसला

कुल मिलाकर, जीएसटी सुधार छोटे उद्योगों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल उनकी दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि टैक्स की जटिलता को भी कम करेगा। हालांकि इससे सरकारी राजस्व में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन लंबे समय में यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और विकास दर को बढ़ावा देगा। मोदी जी का यह कदम स्वदेशी को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह छोटे उद्योगों को नई उड़ान देने का वादा करता है, जिससे न सिर्फ कारोबारी, बल्कि पूरा देश समृद्ध होगा।

– शमशेर खरक
प्रदेश मीडिया सह प्रभारी,
भाजपा हरियाणा

सादगी, ताक़त और आधुनिकता का संगम है मोदी के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा

नीरज कुमार दुबे

इसके विपरीत, कई मंत्रियों ने पुराने वाहन अपनी संपत्ति में शामिल किए हैं। नितिन गडकरी की 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार, विरेंद्र कुमार का 37 साल पुराना स्कूटर और रवनीत बिट्टू की 1997 मॉडल की मारुति, ये सब केवल धातु के ढाँचे नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संपत्ति का विवरण जारी किया गया है। पहली नज़र में यह सूची केवल आभूषण, ज़मीन, गाड़ियाँ और निवेशों का ब्योरा लगती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह भारतीय राजनीति की मानसिकता, सामाजिक प्रतीकवाद और सत्ता की शैली का आईना बन जाती है। सबसे पहले ध्यान आकर्षित करता है जयंत चौधरी का क्रिप्टो निवेश। वह अकेले मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल संपत्ति घोषित की है। उन्होंने करीब 43 लाख रुपये के बिटकॉइन जैसे निवेश किये हैं। यह उस समय में खास महत्व रखता है जब भारत में क्रिप्टो अब भी कानूनी अनिश्चितता में है और RBI लगातार इससे जुड़े जोखिमों की चेतावनी देता रहा है। यह खुलासा दिखाता है कि नए दौर का नेतृत्व जोखिम लेने और नए वित्तीय प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रहा।

इसके विपरीत, कई मंत्रियों ने पुराने वाहन अपनी संपत्ति में शामिल किए हैं। नितिन गडकरी की 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार, विरेंद्र कुमार का 37 साल पुराना स्कूटर और रवनीत बिट्टू की 1997 मॉडल की मारुति, ये सब केवल धातु के ढाँचे नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश हैं। जनता को यह बताना कि नेता अब भी 'साधारण' हैं, विलासिता से दूर हैं और परंपरा को सँजोए हुए हैं। लेकिन इस सादगी के बीच एक और पैटर्न साफ़ झलकता है—हथियारों की मौजूदगी। रिवॉल्वर, पिस्तौल और राइफल घोषित करने वाले मंत्री कम नहीं हैं। यह उस सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है जहाँ ताक़त का प्रदर्शन और व्यक्तिगत सुरक्षा सत्ता के साथ कदमताल करती है।

सबसे बड़ा हिस्सा, अपेक्षा के अनुसार सोने और आभूषणों का है। राव इंदरजीत सिंह के पास 1.2 करोड़ रुपये से अधिक का सोना और हीरे हैं, नितिन गडकरी व एल. मुरुगन के पास भी लाखों के आभूषण हैं। देखा जाये तो भारतीय समाज में आभूषण सदियों से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों का प्रतीक रहे हैं, मंत्रियों की संपत्ति भी इस परंपरा को दोहराती है। मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 27 लाख से अधिक के आभूषण, म्यूचुअल फंड में 19 लाख से ज्यादा और एक दोपहिया वाहन है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास भी रिवॉल्वर, राइफल, ट्रैक्टर और लगभग ₹1 करोड़ के म्यूचुअल फंड हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के पास डबल बैरल गन और रिवॉल्वर तथा 67 लाख से ज्यादा के सोने के आभूषण हैं।

देखा जाये तो इन संपत्तियों का सार्वजनिक खुलासा लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी है। यह जनता को भरोसा दिलाने का प्रयास भी है कि नेता अपनी आर्थिक स्थिति छिपा नहीं रहे। लेकिन इन घोषणाओं का एक दूसरा पहलू भी है कि संपत्ति अब केवल निजी स्वामित्व नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गई है।

बहरहाल, मोदी सरकार के मंत्रियों की घोषित संपत्तियाँ केवल रकम और वस्तुओं का हिसाब नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की बदलती शैली का दस्तावेज़ हैं। यह दस्तावेज़ बताता है कि सत्ता में बैठे लोग जनता को साधारण, शक्तिशाली, पारंपरिक और आधुनिक, सभी रूपों में संदेश देना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या ये संदेश वास्तविक जीवन की सच्चाई हैं या केवल राजनीतिक छवि गढ़ने का प्रयास?

हिंदी दिवस : आंकड़े, अवसर और हमारी जिम्मेदारी

उमेश कुमार साहू

14 सितम्बर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यह दिवस केवल आयोजन या औपचारिकता का प्रतीक भर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या वास्तव में हम हिंदी को उसकी वास्तविक क्षमता और गरिमा के अनुरूप स्थान दिला पा रहे हैं?

हिंदी की स्थिति : आंकड़ों की रोशनी

2011 की भारत की जनगणना बताती है कि 52.83 करोड़ लोग (43.63%) हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। यदि दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 69.15 करोड़ (57.11%) तक पहुँच जाती है। यानी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी सीधे-सीधे हिंदी से जुड़ी है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी हिंदी का दायरा व्यापक है। Ethnologue जैसे भाषाई स्रोतों के अनुसार, हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व स्तर पर 609 मिलियन से अधिक है। यह हिंदी को दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे-तीसरे स्थान पर ला खड़ा करता है। यह तथ्य केवल आँकड़ा नहीं, बल्कि हमारी भाषाई ताक़त का परिचायक है।

डिजिटल युग और हिंदी

इंटरनेट व मोबाइल क्रांति ने हिंदी को अभूतपूर्व अवसर दिया है। जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 729 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता भारतीय भाषाओं में सामग्री पढ़ते-देखते हैं। इसमें शहरी उपयोगकर्ता लगभग 345 मिलियन और ग्रामीण 384 मिलियन हैं। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी भाषा का है। आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और OTT प्लेटफ़ॉर्म्स पर हिंदी कंटेंट का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखता है। यूट्यूब इंडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि सबसे अधिक देखे जाने वाले 100 वीडियो में से लगभग 70–75% हिंदी या हिंदी-प्रधान सामग्री वाले होते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि डिजिटल भारत में हिंदी सिर्फ़ मनोरंजन की भाषा नहीं, बल्कि बाजार और अर्थव्यवस्था की प्रमुख धुरी बन चुकी है।

शिक्षा और प्रशासन : अब भी अंग्रेज़ी की पकड़

परंतु दुखद पहलू यह है कि उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की भूमिका अब भी सीमित है। मेडिकल, इंजीनियरिंग या विधि जैसे विषयों में ज़्यादातर पाठ्यपुस्तकें और शोध सामग्री

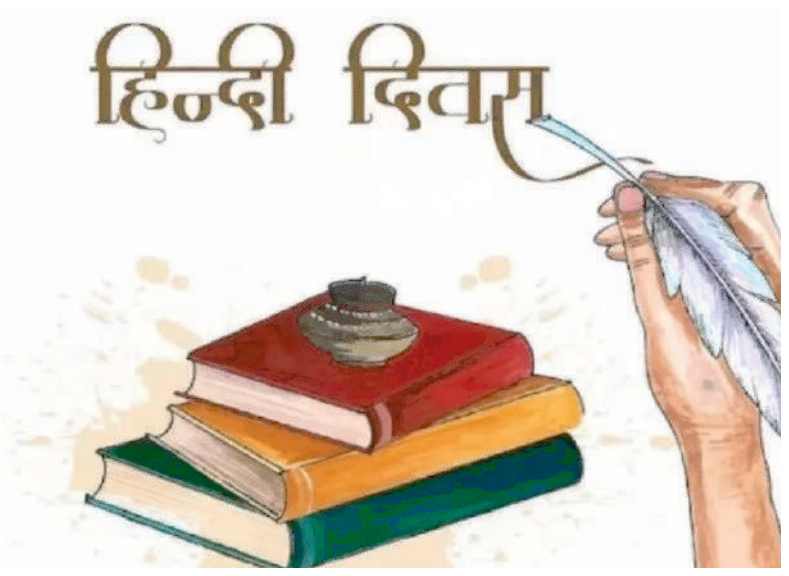

अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप लाखों विद्यार्थी, जिनकी प्राथमिक भाषा हिंदी है, ज्ञान तक सहज पहुँच से वंचित रह जाते हैं। यही नहीं, अदालतों, सरकारी दफ़्तरों और बड़ी कंपनियों में भी अंग्रेज़ी का वर्चस्व स्पष्ट है। हिंदी में आदेश या दस्तावेज़ बनाने की पहल तो होती है, लेकिन उसका प्रयोग व्यवहार में बहुत सीमित है।

विश्व में हिंदी : बढ़ती पहचान

हिंदी का आकर्षण अब सीमाओं से बाहर निकल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और खाड़ी देशों में बसे प्रवासी भारतीय हिंदी को जीवित रखे हुए हैं। Cornell, Columbia, Michigan जैसे कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों में भी छात्रों के बीच हिंदी सीखने की उत्सुकता बढ़ रही है। यह हिंदी के लिए सम्मानजनक अवसर है कि वह संस्कृति और सभ्यता के साथ-साथ व्यापार और ज्ञान-विज्ञान की भाषा बने।

प्रमुख चुनौतियाँ

नीति और व्यवहार का अंतर - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) मातृभाषा आधारित शिक्षा की बात तो करती है, लेकिन विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इसका क्रियान्वयन मुश्किल साबित हो रहा है।

सामाजिक मानसिकता - अब भी समाज में अंग्रेज़ी को "प्रतिष्ठा" और "सफलता" से जोड़ा जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी से अधिक अंग्रेज़ी में दक्ष बनाना चाहते हैं।

गुणवत्ता संसाधन की कमी - विज्ञान, तकनीक और विधि जैसे क्षेत्रों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली हिंदी सामग्री अभी पर्याप्त नहीं है। मानकीकृत तकनीकी शब्दावली और डिजिटल संसाधनों की कमी भी बड़ी बाधा है।

अवसर और समाधान

डिजिटल हिंदी का विस्तार - ब्लॉग, ई-पुस्तकें, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हिंदी में विविध और उच्च-स्तरीय सामग्री तैयार करनी होगी।

तकनीकी शब्दावली का मानकीकरण - AI और मशीन ट्रांसलेशन टूल्स की मदद से जटिल विषयों का अनुवाद आसान बन सकता है।

उच्च शिक्षा में हिंदी - विश्वविद्यालयों को हिंदी माध्यम से शोध व व्याख्यान की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे लाखों छात्रों को ज्ञान तक समान अवसर मिलेगा।

प्रशासनिक सुधार - सरकारी दफ़्तरों और न्यायालयों में हिंदी का व्यवहारिक उपयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

सामाजिक दृष्टिकोण बदलना - यह समझ बनानी होगी कि अंग्रेज़ी सीखना उपयोगी है, पर हिंदी को छोड़ना आवश्यक नहीं। बहुभाषिकता ही आधुनिक भारत की ताक़त है।

क्या पसमांदा समाज को लेकर भाजपा अपनी रणनीति में सफल होगी!

रामस्वरूप रावतसरे

जामिया मिलिया इस्लामिया में पसमांदा समाज पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता दानिश आज़ाद अंसारी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई. इसे ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ ने आयोजित किया था।

इस आयोजन का विषय था ''जाति जनगणना और उसका पसमांदा समाज के सार्वभौमिक विकास पर प्रभाव।'' इसमें भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश चंद्र शर्मा समेत अनेक भाजपा राजनेताओं ने शिरकत की तथा आयोजन को जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर मजहर आसिफ ने संरक्षण प्रदान किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऐसे बहुतेरे कार्यक्रम पसमांदा समाज के अनेक संगठनों, जो भाजपा द्वारा समर्थित हैं, द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में चलाए जा रहे हैं जिसमें जाति जनगणना से पसमांदा समाज को होने वाले विभिन्न फायदों को बताया जा रहा है।

बिहार में चुनाव नजदीक हैं तथा एसआईआर का मुद्दा काफी हावी होता जा रहा है। इस बार का बिहार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष को चुनाव जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले साल के लोकसभा के चुनाव में भी विपक्ष से जितनी उम्मीद थी, उतनी सीट नहीं जीत सकी। इस चुनाव में भी जाति जनगणना का मुद्दा और आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का मुद्दा गति पकड़ रहा है जहां एक तरफ महागठबंधन बिहार में जातिगत सर्वे के आधार पर बढ़ाई गई आरक्षण की सीमा को लागू करवाना चाहता है तथा उसको संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने का दबाव दे रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस मुद्दे पर जाति जनगणना की घोषणा करके शांत बैठा हुआ है।

इस जाति जनगणना को विपक्ष जिस तरह केवल पिछड़ा वर्ग, दलित और अनुसूचित जनजाति से जोड़कर और मात्र अगड़ी जातियों बनाम पिछड़ी जातियों के संदर्भ में देख रहा है. मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहने वाला है। यह बढ़कर मुस्लिम बनाम मुस्लिम भी होने की संभावनाओं को बल देता प्रतीत हो रहा है। इस जनगणना में हर धर्म की जातियों को गिना जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर मुस्लिम धर्म की जाति जनगणना से होगा, जिसे अब तक एक मुस्लिम इकाई और एकमुश्त वोट के रूप में देखा जाता था। जाति जनगणना के बाद यह एकमात्र इकाई के रूप में नहीं रह पाएगा और भाजपा इस विभाजन में सेंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी मालूम पड़ती है।

वैसे तो मुस्लिम समाज में सैद्धांतिक रूप से समानता की बात कही गई है लेकिन भारत में यह उन तमाम जातियां में बटी हुई है जो कि हिंदू धर्म में आते हैं, जैसे धोबी, बढ़ई, दर्जी, नाई, राजपूत, गुर्जर, जाट आदि। इनमें भी काफी हद तक हिंदू धर्म में फैली जाति असमानताएं हैं तथा भेदभाव भी कमोबेश एक समान ही है। इस मुस्लिम समाज में पिछड़े हुए लोगों को पसमांदा मुसलमान कहते हैं तथा इन पिछड़ों को आरक्षण का लाभ, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में भी उसी रूप में मिलता है जैसे अन्य धर्म के पिछड़ों को।

जाति जनगणना से मुस्लिम समाज में फैली जाति व्यवस्था को एक ठोस आंकड़ों का आधार मिल जाएगा। इससे उनमें एक बंटवारे की गुंजाइश बढ़ जाएगी। जब समाज की असमानताओं की जानकारी को एक ठोस प्रमाण मिल जाएगा तो उसको पाटने के लिए अनेक योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों का भला भी हो सकता है।

प्राय देखा गया है कि विपक्षी एवं खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों ने मुस्लिम समाज में जातीय व्यवस्था को तरजीह नहीं दी और उनकी पहचान को सिर्फ इस्लाम तक ही सीमित रखा, जिससे पसमांदा समाज को यथोचित लाभ नहीं मिल सका। इस घाव को भाजपा समय-समय पर किसी ना किसी बहाने कुरेदती रहती है। अब इस पर हमला करने की तैयारी कर रही है।

हाल के वर्षों में दो जगह जातिगत सर्वे हुआ, बिहार और तेलंगाना। बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल मुस्लिम आबादी 17 प्रतिशत है तथा उनमें भी पसमांदा मुसलमान की संख्या 70 फ़ीसदी है जिससे दोनों वर्ग के जनसंख्या में लगभग वही अंतर मालूम पड़ता है जो अंतर हिंदू समाज में उच्च वर्ग तथा अन्य जातियों में है। वहीं तेलंगाना में मुस्लिम की कुल आबादी 12.56 प्रतिशत है। 10.08 प्रतिशत पसमांदा मुस्लिम हैं, अर्थात सवर्ण मुसलमानों की आबादी, जिसमें शेख, सैयद, पठान आदि जातियां आती हैं। मात्र 2.48 ही है अर्थात यहां पर भी 70 प्रतिशत से अधिक आबादी पसमांदा मुस्लिम समाज की ही है।

सीएसडीएस लोकनीति पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार, हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल मुस्लिम वोट का 8 प्रतिशत वोट मिला था तथा राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार लाभार्थी कार्ड का भी इसमें बड़ा योगदान था। जम्मू कश्मीर से पसमांदा गुलाम अली को राज्यसभा सांसद बनाना, उत्तर प्रदेश में पसमांदा समाज से आने वाले दानिश आज़ाद अंसारी को अल्पसंख्यक मंत्री बनाना भाजपा को पसमांदा को अपनी तरफ आकर्षित करने के कदम के रूप में देखा जाता है।

हैदराबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पसमांदा समाज को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करें तथा पसमांदा समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएं।

हाल के दिनों में वक्फ बोर्ड बिल जो पास किया गया उसके पीछे भी भाजपा का यही तर्क था कि वक्फ बोर्ड में ज्यादातर सवर्ण मुस्लिमों की संख्या है तथा इसका मुख्य लाभ पसमांदा समाज के मुस्लिमों या महिलाओं को नहीं मिल पाता है तथा इसका विरोध भी सवर्ण मुस्लिम ही कर रहे हैं। वक्फ सुधार बिल में यह सुनिश्चित गया किया गया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ-साथ पिछड़े मुसलमान को भी सदस्य बनाया जाएगा, तथा इसका स्वागत अनेक पसमांदा समाज के संगठनों ने किया।

जानकारों की माने तो जाति जनगणना होने से अनेक प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं के आंकड़े बाहर आ जाएंगे जिसे लेकर पसमांदा समाज अपनी राजनीतिक भागीदारी की मांग के लिए एक ठोस आधार भी दे सकता है। इससे अब तक जो पार्टियां जिन्हें मुस्लिम समाज वोट कहता आया है, अब वे उन्हें (पसमांदा समाज को) मुस्लिम समाज में हिस्सेदारी देने पर मजबूर हो सकती हैं। भाजपा यही तो चाहती है। हालांकि, भाजपा के लिए पसमांदा राजनीति को धार देना इतना आसान नहीं होगा लेकिन भाजपा ने पसमांदा मुसलमानों को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। भाजपा का वैचारिक स्तर पर जामिया मिलिया इस्लामिया में पसमांदा समाज पर कार्यक्रम आयोजित करना इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है।

राष्ट्रभाषा नहीं, सिर्फ राजभाषा बनकर रह गई हिंदी

कुमार कृष्णन

14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में इसी तारीख को संविधान सभा ने एक लंबी और सजीव बहस के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया था। भारतीय संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 343 से 351 तक इसी विषय के बारे में है। अनुच्छेद 343 (1) में यह घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। लेकिन अनुच्छेद 343 (2) और उसके बाद के अनुच्छेदों को पढ़ने से पता चलता है कि भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में राजभाषा के मुद्दे को बहुत कठिन और जटिल रास्ते से होकर गुजरना है क्योंकि देश के सरकारी संस्थानों में अंग्रेजी में निर्धारित कानूनों, नियमों और विनियमों का ही वर्चस्व है।

इसका एक समझौता के रूप में वर्णन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां, संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाने वाले या पारित सभी विधेयकों और अधिनियमों के अधिकृत पाठ, संविधान के तहत पारित सभी आदेश / नियम / कानून और विनियमों को अंग्रेजी में ही होना चाहिए (जैसा औपनिवेशिक भारत में था)। 17 फरवरी, 1987 को संविधान (58वां) संशोधन अधिनियम के पारित होने तक संविधान (संशोधनों में शामिल) का कोई अद्यतन संस्करण संशोधनों के साथ हिंदी में जारी नहीं किया जा सकता था। विभिन्न कारणों से एक राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। यही कारण है कि 78 वर्षों के बाद भी हिन्दी अंग्रेजी की जगह लेती हुई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कार्य के लिए केवल 15 साल का समय दिया था।

राजभाषा की अवधारणा राज्य के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सशस्त्र बलों आदि से संबंधित है। हालांकि, देश अपने सरकारी संस्थानों से कहीं बड़ा है। भारत में महात्मा गांधी ने जो जन जागरण किया वह संस्थानों से बाहर हुआ था। उनका असहयोग आंदोलन या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कांग्रेस का चुनाव में भाग लेने के उनके विरोध से यह पता चलता है कि उन्होंने देश की अपने संस्थानों पर निर्भरता को नकार दिया था। गांधीजी औपनिवेशिक भारत में उसके राज्य तंत्र के बीच की खाई और उसके लाखों लोगों के बारे में पूरी तरह जागरूक थे। वे भारत की बजाय भारतीय राष्ट्र को संबोधित करना चाहते थे। गांधीजी ने ऐसा करने के लिए अंग्रेजी की बजाय लोगों की भाषा का उपयोग करने का तरीका अपनाया।

भाषा का यह प्रश्न गांधीजी के स्वदेशी अभियान का अभिन्न अंग था। उन्होंने यह समझ लिया था कि लोग अपनी भाषा के जरिए ही स्वराज के मिशन में शामिल हो सकते हैं। इसलिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, गांधी ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। प्रताप (हिन्दी) में 28 मई, 1917 को प्रकाशित उनके लेख में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत की गई थी।15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर के कटहलबाड़ी क्षेत्र में बिहारी छात्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। देशरत्न डॉ राजेन्द्र प्रसाद के निर्देश पर बिहारी छात्रों के संगठन का काम लालूचक के श्री कृष्ण मिश्र को सौंपा गया था। बिहारी छात्रों के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था-' मुझे अध्यक्ष का पद देकर और हिन्दी में व्याख्यान देना और सम्मेलन का काम हिन्दी में चलाने की अनुमति देकर आप बिद्यार्थियों ने मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया है। इस सम्मेलन का काम इस प्रांत की भाषा में ही और वही राष्ट्रभाषा भी है- करने का निश्चय दूरन्वेषी से किया है।' इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू का भाषण अंग्रेजी से हिन्दी अनुदित होकर छपा था। यह सम्मेलन आगे चलकर भारत की राजनीति, विषेषकर स्वतंत्रता संग्राम में राजनीति का कॅानवास बना, जिससे घर-घर में स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद करना मुमकिन हो सका। वही प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेलकर ने इस सम्मेलन के भाषण को राष्ट्रीय महत्व प्रदान कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की बुनियाद डाली थी। बाद में इसी कटहलबाड़ी परिसर में मारबाड़ी पाठशाला की स्थापना हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी को जनमानस की भाषा कहा था।उन्होंने 1918 में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए कहा था।

बाजरा बनाम क्विनोआ: वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है?

विजय गर्ग

लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई): बाजरा में आमतौर पर क्विनोआ सहित कई अन्य अनाजों की तुलना में कम जीआई होता है। इसका मतलब है कि वे रक्त शर्करा के स्तर में स्पाइक्स और क्रैश को रोकते हुए धीरे-धीरे रक्तप्रवाह में चीनी छोड़ते हैं। भूख के प्रबंधन और लालसा को कम करने के लिए स्थिर रक्त शर्करा महत्वपूर्ण है। धीमी गति से रिलीज होने वाली कार्ब्स: बाजरा में जटिल कार्बोहाइड्रेट निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो सक्रिय जीवन शैली के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और भूख के दर्द को रोक सकते हैं।

बाजरा और क्विनोआ दोनों वजन घटाने के लिए उत्कृष्ट विकल्प हैं, क्योंकि वे पौष्टिक, लस मुक्त और फाइबर में उच्च हैं। हालांकि, उनके पास अलग-अलग पोषण प्रोफ़ाइल हैं जो आपके विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर एक संभावित बेहतर विकल्प बनाते हैं। यहाँ बाजरा बनाम का टूटना है। वजन घटाने के लिए क्विनोआ: बाजरा बाजरा छोटे-छोटे अनाज अनाज का एक समूह है। वे वजन घटाने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं:

उच्च फाइबर सामग्री: बाजरा में आमतौर पर क्विनोआ की तुलना में अधिक फाइबर होता है। यह वजन घटाने के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि फाइबर परिपूर्णता और तृप्ति की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे समग्र कैलोरी सेवन को कम करने और अधिक खाने से रोकने में मदद मिलती है।

लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई): बाजरा में आमतौर पर क्विनोआ सहित कई अन्य अनाजों की तुलना में कम जीआई होता है। इसका मतलब है कि वे रक्त शर्करा के स्तर में स्पाइक्स और क्रैश को रोकते हुए धीरे-धीरे रक्तप्रवाह में चीनी छोड़ते हैं। भूख के प्रबंधन और लालसा को कम करने के लिए स्थिर रक्त शर्करा महत्वपूर्ण है।

धीमी गति से रिलीज होने वाली कार्ब्स: बाजरा में जटिल कार्बोहाइड्रेट निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो सक्रिय जीवन शैली के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और भूख के दर्द को रोक सकते हैं।

पोषक तत्व घनत्व: बाजरा मैग्नीशियम, फास्फोरस और बी विटामिन सहित विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो समग्र चयापचय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। क्विनोआ एक छद्म अनाज बीज है जो इसकी अद्वितीय पोषण संरचना के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में

उत्कृष्टता प्राप्त करता है:

पूर्ण प्रोटीन स्रोत: क्विनोआ कुछ पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में से एक है जिसमें सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जिससे यह रूपूर्ण प्रोटीनरू बन जाता है। प्रोटीन वजन घटाने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुबला मांसपेशियों को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है, जो चयापचय को बढ़ाता है और अधिक कैलोरी जलाता है। यह फाइबर के समान तृप्ति भी बढ़ाता है।

उच्च प्रोटीन सामग्री: क्विनोआ में अधिकांश बाजरा की तुलना में प्रति सेवारत अधिक प्रोटीन होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जो शारीरिक रूप से सक्रिय हैं या शाकाहारी / शाकाहारी आहार का पालन कर रहे हैं और पर्याप्त प्रोटीन का सेवन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

पोषक-समृद्ध: क्विनोआ लोहे, मैग्नीशियम और जस्ता जैसे आवश्यक खनिजों से भरा हुआ है, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक स्वस्थ चयापचय का समर्थन कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा बेहतर है? सबसे अच्छा विकल्प आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और वरीयताओं पर निर्भर करता है:

बाजरा चुनें अगर ... आपका प्राथमिक लक्ष्य आपके फाइबर का सेवन बढ़ाना है और आपके कैलोरी सेवन को नियंत्रित करने के लिए अधिक समय तक भरा हुआ महसूस करना है। बाजरा का निचला जीआई रक्त शर्करा के स्तर और लालसा के प्रबंधन के लिए भी बहुत मददगार हो सकता है।

क्विनोआ चुनें अगर ... आप मांसपेशियों के रखरखाव और एक बढ़ाया चयापचय का समर्थन करने के लिए एक पूर्ण प्रोटीन स्रोत चाहते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आप शक्ति प्रशिक्षण में संलग्न हैं या संयंत्र-आधारित प्रोटीन विकल्प चाहते हैं। फैसला: वजन घटाने के आहार के लिए दोनों उत्कृष्ट विकल्प हैं। एक दूसरे को चुनने के बजाय, आप विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों और लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने भोजन में बाजरा और क्विनोआ दोनों को शामिल कर सकते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण अक्सर दीर्घकालिक स्वास्थ्य और वजन प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी होता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

किराए पर दादा-दादी

विजय गर्ग

हाल में जापान में 'ओके ओबाचान' नाम की सेवा शुरू की गई है जिसमें 60 से 94 साल तक की महिलाएं किराए पर दादी का रोल निभाती हैं। कोई परिवार उन्हें कुछ घंटों के लिए घर बुलाता है, वे बच्चों की देखभाल करती हैं, खाना बनाती हैं, बातें करती हैं और जरूरत पड़ने पर रिश्तों या जीवन से जुड़े सुझाव भी देती हैं। इस सेवा का उद्देश्य दोहरा है - बुजुर्ग महिलाओं को आय और उद्देश्य देना और अकेलेपन से जूझते युवाओं एवं परिवारों को मां या दादी के प्रेम का अनुभव कराना। भारत से भी इसी तरह की खबर सामने आई जब आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम ने हाल में में रेंट ए ग्रैंडपैरेंट' नाम की सेवा शुरू की। यहां परिवार महीने भर के लिए 11,000 रुपये देकर किसी बुजुर्ग को घर ला सकते हैं। आश्रम का तर्क है कि इससे बच्चों को दादा-दादी या नाना-नानी का प्यार मिलेगा और बुजुर्गों को घर जैसे माहौल में रहने और आय का अवसर मिलेगा।

भारत की पारंपरिक पारिवारिक संरचना हमेशा से संयुक्त परिवार पर आधारित रही है। यहां दादा-दादी बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा माने जाते हैं। कहानियों, लोकगीतों और अनुभवों से वे बच्चों को जीवन जीने की कला और मूल्य सिखाते हैं, लेकिन शहरीकरण, नौकरियों के दबाव और करियर की दौड़ ने पारिवारिक ढांचे को बदल दिया है। अब महानगरों और शहरों में अधिकतर परिवार एकल रूप में रहते हैं। बच्चे दादा-दादी के साथ बड़े होने का अनुभव खो रहे हैं और बुजुर्ग भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें 'रैंट ए ग्रैंडपैरेंट' जैसी सेवा जन्म ले रही है।

भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2050 तक लगभग 20 प्रतिशत आबादी 60 साल से ऊपर होगी। ऐसे में वृद्धाश्रमों और देखभाल केंद्रों पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी ओर, बच्चे अपने दादा-दादी के बिना बड़े हो रहे हैं जिससे उनकी सांस्कृतिक जड़ें कमजोर हो रही हैं। इस लिहाज से यह सेवा कुछ हद तक एक व्यावहारिक समाधान लग सकती है, लेकिन स्थायी समाधान यह नहीं है। दरअसल भारत की जरूरत केवल किराए पर दादा-दादी नहीं है, बल्कि ऐसे प्रयास हैं, जो स्वाभाविक रूप से पीढ़ियों को जोड़ें। मोहल्लों और सोसायटी स्तर पर कार्यक्रम, स्कूलों में बुजुर्गों की भागीदारी, सामुदायिक केंद्रों में पीढ़ियों का संवाद ऐसे रास्ते हैं जिनसे बच्चों और बुजुर्गों को जोड़ना संभव है। सरकार और संस्थानों को भी चाहिए कि बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार के अवसर और सामाजिक जीवन की व्यवस्था करें, ताकि उन्हें मजबूरी में किराए पर जाना न पड़े।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। उन्हें समाज और परिवार की जिम्मेदारी के तहत ही फिर से जीवित करना होगा।

डिजिटल दौर में शिक्षक की बढती जिम्मेदारी

विजय गर्ग

आज का समय डिजिटल प्रारूप का है। इसने छात्रों को सीखने के नए अवसर दिए हैं, लेकिन साथ ही शिक्षकों के सामने अनेक चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। डिजिटल युग में शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उन्हें तकनीक, प्रबंधन, मूल्य- निर्माण और मनोवैज्ञानिक संतुलन का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है तकनीकी ज्ञान एवं उसका प्रयोग। डिजिटल युग में शिक्षकों के लिए केवल विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उन्हें तकनीक से लैस होना अनिवार्य हो गया है। दूसरी बड़ी चुनौती है व्यक्तिगत संपर्क और भावनात्मक जुड़ाव का अभाव। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र के बीच एक भावनात्मक संबंध होता था, जिससे शिक्षक न केवल ज्ञान देता था, बल्कि छात्र के व्यक्तित्व निर्माण, मूल्य शिक्षा और जीवन कौशल में भी योगदान करता था। लेकिन डिजिटल माध्यम में यह संबंध कमजोर पड़ता जा रहा है। वर्चुअल क्लासरूम में शिक्षक छात्रों की भावनाओं, उनके मनोभावों और सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। इससे शिक्षा में मानवीय स्पर्श कम हो रहा है। यह चुनौती इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि शिक्षा केवल तथ्यों का आदान- प्रदान नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी है।

डिजिटल डिवाइस और ध्यान भटकाव भी शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती है। आनलाइन क्लास के दौरान छात्र अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं। क्लास में कई छात्र चुपके से

स्मार्टफोन आदि लेकर आते हैं और इंटरनेट मीडिया या वीडियो गेम में व्यस्त रहते हैं। शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि छात्र वास्तव में कितनी गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। इस कारण शिक्षण की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध असीमित जानकारी का सही और गलत में अंतर करना भी छात्रों के लिए मुश्किल है। ऐसे में शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह छात्रों को विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों की पहचान कराना सिखाए। एक अन्य चुनौती है मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना। आनलाइन परीक्षाओं के दौरान नकल की आशंका अधिक रहती है। इससे न केवल मूल्यांकन की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, बल्कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय भी होता है। भाषा और संचार का बदलता स्वरूप भी शिक्षकों के लिए चुनौती है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षक पर बढ़ता मानसिक और पेशेवर दबाव। डिजिटल युग में छात्रों और अभिभावकों की अपेक्षाएं कई गुना बढ़ गई हैं।

हालांकि यह कहना गलत होगा कि डिजिटल युग केवल चुनौतियां लाया है। इसने शिक्षकों को नए अवसर भी दिए हैं। वे अब वैश्विक ज्ञान से जुड़ सकते हैं, नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं और छात्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे में शिक्षकों को इन चुनौतियों का समाधान खोजना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार और शैक्षणिक संस्थाएं शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, उन्हें तकनीकी साधन उपलब्ध कराएं और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी पहल करें।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

अभिव्यक्ति के आयाम

विजय गर्ग

प्रदर्शन के मूल में उन्नति होती है। यह भी मान सकते हैं कि प्रदर्शन तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। बढ़ने और इससे आगे बढ़ने की लालसा जीवन के क्रम हैं। जीवन में हर हाल में जागृति रहे, इसलिए प्रदर्शन होते रहने चाहिए। जागरूक व्यक्ति नई से नई राह पर चल कर एक से एक उपलब्धियां पा लेता है। ऊंचे से और ऊंचा बढ़ने को कृतसंकल्प रहता है। इसे ही सही विकास की राह पर चलना कहते हैं। विकास और उन्नति या तरक्की कोई अलग चीज नहीं, एक दूसरे के पर्याय हैं। शब्दों के मायाजाल पर मोहित होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रदर्शन को शायद इसीलिए प्रगति सूचक कहा जाता है कि इसमें खुद को अभिव्यक्त किया जाता है।

किसी भी प्रदर्शन से पूर्व नई सकारात्मक सोच लानी होती है। सिर्फ अचानक ही आसमान की ओर देख लेने से कुछ नहीं होता। कम से कम अपने ऊपर आत्मविश्वास के स्तर को कुछ ऊंचा रखना पड़ता। कुछ लोग उसे अहं के रूप में देख सकते हैं, लेकिन उसी आरोप को संभालना पड़ता है। शुरुआत में दृष्टि एक बिंदु पर न टिक कर इधर-उधर घूमती है, लेकिन सब कुछ देख लेने की फौरी जिज्ञासा इतनी प्रबल होती है कि जितना दिखता है, उससे और अधिक देख लेना चाहती है। इसे सृजक के नजरिए से देखा जा सकता है। दुनिया भर के सृजन के स्रोत ऐसे ही बनते हैं और बढ़ते जाते हैं। उमंगों की हिलोरों से एक खास उमंग जब उठती है ऊपर, तो वह आसमान छू लेने की चाहत रखती है। इसे ही मुहावरे में कहा जाता है आसमान में छेद करना। यह मूलतः प्रदर्शन का परिणाम है। इसलिए यह आवश्यक है कि आगे बढ़ने की निरंतरता सदा बनी रहे।

आमतौर पर प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति यानी 'प्रोग्रेस रिपोर्ट- कार्ड' बनाया जाता है, जिसे 'रिजल्ट कार्ड' या परिणाम - पत्र भी कहते हैं। इसे अच्छे-बुरे या उन्नति - अवनति का परिणाम प्रदर्शन - पत्र भी कह सकते। यहां मुख्य उद्देश्य केवल प्रदर्शन से है। ये अक्सर जीवन में पथ-प्रदर्शक का कार्य कर जाते हैं। अनजाने में आई जटिलताओं का निवारण भी इन्हीं के आधार पर केंद्रित होता है।

आम जीवन में ही नहीं, बल्कि देश - विदेश की सरकारें भी स्वीकार्य प्रदर्शन करवाती हैं। अंतर इतना होता है कि कहीं दिखाने के लिए तो कहीं दूसरे को डराने-धमकाने के लिए ये प्रदर्शन किए जाते हैं। हालांकि प्रदर्शन कोरे प्रदर्शन नहीं होते, न ही ये मूक-बधिर होते हैं, बल्कि कुछ जागरूक लोगों की बुलंद आवाज में भी हो सकते हैं कि जिससे बड़े से बड़े सदन हिल जाते हैं। गहराई से देखा जाए तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आपसी सौहार्द बना रहता है। टीवी पर एक पारिवारिक धारावाहिक में अलग-अलग जाति-धर्म-भाषा के परिवार हंसी-खुशी से रहते दिखाए जाते हैं। वे बात-बेबात लड़ाई-झगड़े भी करते हैं। फिर सुलह- दोस्ती कर एक सीध में हंसते हु खड़े दिखते हैं। ये खड़े होने की उनका शैली ही खास प्रदर्शन है। इनके चेहरे दर्शकों की ओर मुंह किए हुए अर्ध-गोलाई में होते हैं। बहरहाल, प्रदर्शन एक समान हो और उसका फल भी एक समान आए, यह तब संभव है जब एक समान शिक्षण-प्रशिक्षण हो, कोई भेदभाव न रखा जाए। बच्चों को एक स्कूल - परिधान पर्याप्त नहीं होते। उन्हें समान अवसर भी मिलना चाहिए। इसलिए कई विद्यालयों नें अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 'यू' अक्षर, यानी अर्धगोलाकार आकृति में बैठाना शुरू कर दिया है। इसके फलस्वरूप हर विद्यार्थी अपने शिक्षक के सामने होता है, उनसे सवाल-जवाब या बातचीत भी कर सकता है। इससे वह अपने शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर कर सकता है। एक-दूसरे के पीछे बैठने की मानसिकता कभी भी आगे, और आगे बढ़ने को प्रेरित नहीं करती।

सब जानते हैं स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे मौकों पर देश की जनता को संबोधित किया जाता है। यह भी सरकार की विविध उपलब्धियों के प्रदर्शन का ही मौका होता है। जनसमूह इसे देख - सुन कर मान भी लेता है। इस अवसर पर दुनिया को एक कूटनीति के तहत अपनी ताकत से परिचित भी कराना होता है। विभिन्न झांकियां विकास की कहानियां प्रदर्शित करती दिखती हैं। चूंकि प्रदर्शन विकास के संदर्भ में होते हैं, इसलिए कई लोगों के लिए इसका अध्ययन स्वाभाविक हो जाता है। यों प्रदर्शन का इतिहास बहुत पुराना है। जहां तक लोकतांत्रिक प्रदर्शनों की बात है, इनकी जगहें बदलती रही हैं। जो प्रदर्शन कभी किसी शहर के केंद्र में हुआ करते थे, उनके लिए अब उसी शहर के किसी किनारे-कोने में जगह तय कर दी गई है। चूंकि बेबस जनता का मूल अधिकार होता है प्रदर्शन करना, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना, तो उधर जिम्मेदार सरकार का भी दायित्व बनता है इन प्रदर्शनों को संरक्षित और सुरक्षित रखना। जिस देश में प्रदर्शन जिंदा रहते हैं, वहां लोकतंत्र कभी मरता नहीं।

प्रदर्शन का दर्शन - शास्त्र समझने के लिए पीछे की ओर भी देखा जा सकता है। गांधीजी के लिखे को केवल याद करने से नहीं चलेगा, उन्हें संजीदगी से पढ़ने और समझने की जरूरत है। यह जानना चाहिए कि ब्रिटिश सत्ता के दौरान भारत ने गांधी जी की प्रेरणा से किस तरह अपनी स्वतंत्रता की मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया था और आखिरकार इन्हीं से निकले संदेशों के संकेत समझते हुए, अहिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अंग्रेज यहां से चले गए। यानी प्रदर्शन की दिशा सकारात्मक हो, तो वह देश - दुनिया में स्थायी अध्याय की रचना कर सकता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

चुनौतियों के बीच शिक्षक

विजय गर्ग

भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है'। सार्वभौमिक प्रतीत होती इस पंक्ति के साथ कोठारी आयोग ने अपनी विस्तृत रपट 1964 में लिखी और शायद ही सोचा होगा कि इसके छह दशक बाद भी यह भविष्य उन कक्षाओं में रचा जा रहा होगा, जहां मार्गदर्शन के लिए अध्यापक की बाट देखी जा रही है। आज बढ़ती संख्या वाली कक्षाएं अपनी और राष्ट्र की तकदीर लिखने को तैयार बैठी हैं, लेकिन उनमें वह अभिप्रेरणा नहीं है, जो शिक्षक की उपस्थिति से आती है। शिक्षक, जिसे भविष्य गढ़ने का शिल्पी कहा गया, इन कक्षाओं में कम होते जा रहे हैं। परिणाम यह है कि लाखों बच्चे बिना किसी मार्गदर्शन के अपनी किस्मत और देश का भविष्य अंधेरे में गढ़ने को विवश हैं।

हाल ही में आई एक खबर में यह दावा किया गया कि भारत में एक करोड़ शिक्षक चौबीस करोड़ बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यह अनुपात शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से आदर्श है, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी अच्छी नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश- ये दस राज्य देश की कुल आबादी का लगभग सत्तर फीसद हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज आंकड़े दर्शाते हैं कि पूरे प्रदेश में 1,32,855 सरकारी स्कूलों को 6,03,441 शिक्षक संभाल रहे हैं। औसतन देखें तो हर स्कूल में 4.5 शिक्षक नियुक्त हैं। यहीं से असमानता की असली तस्वीर सामने आती है। इन्हीं आंकड़ों में यह भी दर्ज है कि 8,866 स्कूल ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात है और इन स्कूलों में 6,11,950 बच्चे पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को औसतन उनहत्तर बच्चों को 'पढ़ाने' की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अन्य नौ सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल 10,17,660 सरकारी स्कूलों में से 1,10,971 स्कूल ऐसे हैं, जहां पूरे विद्यालय की बागडोर केवल एक ही शिक्षक के हाथ में है।

'शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं'। यह कहावत आज की हकीकत में कितनी बेमानी लगती है, जब देश के सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षकों की कमी है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, देश में लगभग दस लाख शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है, जिनमें से चार लाख शिक्षकों की जरूरत तो केवल प्राथमिक स्तर पर ही है। हालांकि, संख्या के हिसाब से यह कोई असंभव कार्य नहीं है। ठोस कदम उठाए जाएं, तो एक वर्ष के भीतर ही इन रिक्तियों को भरा जा सकता है। मगर यह न केवल शिक्षण के पेशे के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के प्रति उपेक्षा भी करता है। भले ही भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का हस्ताक्षरकर्ता है, पर पिछले एक दशक से शिक्षक भर्ती और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लगातार अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर बार कुछ वर्ष में ही शिक्षक और शिक्षा पाठ्यक्रम बिना किसी स्पष्ट दृष्टि के लगातार बनाए और बदले जाते रहे हैं। नीति-निर्माताओं की अटपटी योजनाओं के चलते आज भी इस पर स्पष्टता नहीं है कि एक व्यक्ति को बेहतर शिक्षक बनने के लिए किस तरह की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षा क्षेत्र में सेवा की स्थिति और वेतनमान की समस्या आज गंभीर होती जा रही है और इसके निदान के संकेत नहीं मिल रहे।। भर्ती प्रक्रिया की अनवरत देरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी शिक्षण पेशे को अरुचिकर बनाती जा रही है। नतीजतन, प्रतिभाशाली और योग्य युवा इस क्षेत्र में आने से कतराते हैं। सवाल है कि जब भविष्य गढ़ने वाले स्वयं ही असुरक्षा और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हों, तो शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य किस आधार पर सुरक्षित माना जाए?

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर लिए गए नीतिगत निर्णय स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पेशेवर मानकों (एनपीएसटी) और हर वर्ष पचास घंटे की अनिवार्य सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) जैसी पहल शिक्षण को सशक्त बनाने के बजाय बोझिल बना रही हैं। ये कदम अतिरिक्त नौकरशाही बोझ बनकर उभर रहे हैं, जो उनकी स्वायत्तता को कमजोर करते हुए मनोबल गिरा रहे हैं।

नीतिगत विफलताओं का बोझ सीधे शिक्षकों के कंधों पर डालने से पहले यह जरूरी है कि नीतियों पर फिर से सोच-विचार किया जाए। कागजों में शिक्षकों की तुलना गोविंद से करने की भावपूर्ण भाषा का सहारा लेने के बजाय उन्हें वास्तविक सम्मान, गरिमा और पेशेवर स्वायत्तता मिले। जब तक शिक्षा प्रणाली में ऐसे मौलिक बदलाव नहीं होंगे, तब तक शिक्षक महज आज्ञाकारी वेतनभोगी कर्मचारी बनकर रहेंगे और अपने नियंताओं की वैचारिक प्राथमिकताओं और आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

इक्कीसवीं सदी में शिक्षक होना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार कर्तव्य बन चुका है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सूचनाओं तक पहुंच को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन उसे जीवंत, प्रेरणादायी और परिवर्तनकारी बनाने के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि वह प्रेरणास्रोत, मार्गदर्शक और व्यक्तित्व निर्माता होता है जो विद्यार्थियों को सोचने, सवाल करने और खुद को जानने के लिए प्रेरित करता है। अगर आज हम इस मानवीय क्षमता में निवेश नहीं करेंगे, तो एक ऐसी व्यवस्था बनेगी, जहां भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में बिना किसी मार्गदर्शन के एक भ्रम की दुनिया में गढ़ा जा रहा होगा।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

जनसांख्यिकीय पारी: क्या भारत उम्र बढ़ने में बहुत तेज है

विजय गर्ग

कई अन्य देशों की तुलना में भारत की आबादी बहुत तेज नहीं है, लेकिन इस जनसांख्यिकीय बदलाव की गति तेज हो रही है। जबकि देश अभी भी अपेक्षाकृत युवा है, प्रजनन दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण इसकी जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल जल्दी से बदल रही है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर और काफी चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। जनसांख्यिकी पारी भारत एक प्रमुख जनसांख्यिकीय संक्रमण के बीच है। लंबे समय तक, देश की आबादी को युवा लोगों के व्यापक आधार और अपेक्षाकृत कम संख्या में बुजुर्गों की विशेषता थी। यह पारंपरिक जनसंख्या पिरामिड में परिलक्षित होता है। हालांकि, यह बदल रहा है।

गिरती प्रजनन दर: भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पीढ़ी के पास खुद को बदलने के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं हैं। 1950 के दशक में टीएफआर 6.0 से अधिक था, लेकिन अब लगभग 1.9 है।

बढ़ती जीवन प्रत्याशा: बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए धन्यवाद, भारतीय लंबे समय तक रह रहे हैं। पिछले

दशकों में जीवन प्रत्याशा में काफी वृद्धि हुई है।

बढ़ती बुजुर्ग जनसंख्या: कम जन्मों और अधिक समय तक रहने वाले लोगों के संयोजन का अर्थ है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। इस समूह को 2025 में लगभग 11% से 2050 तक 20% से अधिक होने का अनुमान है। शिफ्ट के निहितार्थ इस जनसांख्यिकीय बदलाव के दो प्रमुख निहितार्थ हैं: जनसांख्यिकीय लाभांश और एक उम्र बढ़ने वाले समाज की चुनौतियां। जनसांख्यिकीय लाभांश वर्तमान में, भारत एक रजनसांख्यिकीय लाभांशर का सामना कर रहा है, एक ऐसी अवधि जहां कामकाजी आबादी (15-64 वर्ष) आश्रित आबादी (बच्चों और बुजुर्गों) से बड़ी है। यह आर्थिक विकास के लिए एक अनूठा अवसर बनाता है। कार्यबल में अधिक लोगों और समर्थन के लिए कम आश्रितों के साथ, देश में बचत, निवेश और उत्पादकता में वृद्धि की क्षमता है। हालांकि, इस लाभांश को साकार करना स्वचालित नहीं है। इसके लिए रणनीतिक निवेश और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है:

नौकरियां बनाएं: बढ़ती कार्यबल को अवशोषित करने के लिए अर्थव्यवस्था को पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसके बिना, लाभांश एक जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है, जिससे व्यापक बेरोजगारी और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है।

शिक्षा और कौशल में सुधार: एक बड़ा कार्यबल केवल एक संपत्ति है यदि यह कुशल और उत्पादक है। आधुनिक, प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए भारत की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है।

ओडिशा के छह शहरों में चलेगी 'आम बस'

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन (सीआरयूटी) ने ओडिशा के छह और शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) चलाने की योजना बनाई है। ये ई-बसें राज्य में 'आम बस' सेवाओं के विस्तार के तहत शुरू की जाएँगी। सीआरयूटी की 50वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।इन ई-बसों को क्योंझर, बारीपदा, अंगुल, झारसुगुड़ा, बेरहामपुर और संबलपुर में संचालित करने की योजना है।सीआरयूटी ने एक बयान में कहा कि सभी नई बसें यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नवीनतम चालक सहायता प्रणाली (एडीएएस) से लैस होंगी।

सीआरयूटी ने कहा कि पुरी के समांगा में ई-बसों के लिए एक आधुनिक डिपो स्थापित किया जाएगा, जिससे तीर्थ नगरी में बस संचालन में सुविधा होगी।अधिकारियों के अनुसार, सीआरयूटी ने 290 ई-बसों सहित 670 'आम बसों' की एक अत्यधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित की है। यह 1,399 किलोमीटर लंबे नेटवर्क में 2,099 बस स्टॉप के साथ 115 मार्गों पर परिचालन करती है। प्रतिदिन 3 लाख से अधिक यात्री इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं।

डिजिटल परिवर्तन के तहत, सीआरयूटी ने 'आम बस' ऐप, एटीवीएम, 'आम बस' कार्ड, ओडिशा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और व्हाट्सएप-आधारित टिकटिंग प्रणाली शुरू की है।

इससे पहले, राज्य सरकार ने 'आम बस' टिकटों और चिल्का झील पर नौका सेवाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी।

झारखंड में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यारंभ, के0 रविकुमार ने जिलों के दिया निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

राची। बिहार के बाद झारखंड में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन , जल्द ही शुरू होने जा रहा है . राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर आवश्यक निर्देश साझा किए. उन्होंने कहा कि 17 सितंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का सघन संयुक्ति करण (रेशनलाइजेशन) पूरा कर रिपोर्ट जमा की जाए. साथ ही 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान अविलंब सुनिश्चित करना अनिवार्य है.

मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि अधीनस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर और बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाए. एसआईआर के दौरान जनता को पूरी जानकारी मिले और स्वीप के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाए. इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता और उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर भी मौजूद थे.झारखंड पर्यट

2003 में किए गए विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई मतदाता सूची की कॉपी अब सिईओ झारखंड की वेबसाइट पर आम लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है. इसके अलावा 18 सितंबर से यह सूची बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालयों में भी देखी जा सकेगी. राज्य के बाहर रह रहे मतदाता भी संबंधित राज्य की मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते

एसआईआर को लेकर झारखंड कांग्रेस भी सतर्क हो गई है. कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर सुनिश्चित किया कि बिहार में हुई गलतियों को झारखंड में न दोहराया जाए. कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि बिहार में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, लेकिन फिर भी नाराजगी बनी रही.

..झारखंड कांग्रेस ने 2003 की मतदाता सूची की एक प्रति मांगी है, ताकि उसी आधार पर आगामी एस आईआर में सभी योग्य मतदाताओं के नाम सही तरीके से जोड़े जा सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का निधन हो गया है या जो राज्य से बाहर हैं, उनका नाम हटाना चाहिए, लेकिन किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि एसाईआर के दौरान अधिकारियों को ध्यान रखना होगा कि मतदाता सूची के सभी डेटा गहनता से जांचे जाएं और किसी भी त्रुटि की संभावना न रहे. इस प्रक्रिया से पहले सभी मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन और संबंधित कर्मचारियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली जाएगी

.एसआईआर की प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक सटीक और भरोसेमंद होगी, जिससे चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी. झारखंड सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जनता को किसी तरह की असुविधा न हो.

इस तरह, झारखंड में एसाईआर के माध्यम से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, समय पर रेशनलाइजेशन और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि हर योग्य मतदाता को वोट का अधिकार मिले और सूची में कोई त्रुटि न रहे. कांग्रेस की सतर्कता और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश इसे और प्रभावी बनाएंगे।

प्रफुल्ल मलिक बीजद से निलंबित , कोंग्रेस में जा सकतें !

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : बिजेड़ी पार्टी में गुटबाजी अब चरम पर पहुँच गई है। एक के बाद एक नेता और एक नेत्री पार्टी और पार्टी नेताओं के खिलाफ बवाल मचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। वो ये कि वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रफुल्ल मलिक को बीजेडी से निलंबित कर दिया गया है।हालांकि, निलंबन के बारे में श्री मलिक ने कहा कि मैंने आज सुबह ही बीजद से इस्तीफा दे दिया है।

गुरुवार को श्री मलिक ने बीजद को चेतावनी दी थी। श्री मलिक ने कहा, ₹अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो मैं पार्टी छोड़ दूँगा।₹ इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मैं अब बीजद में हूँ। इसलिए मैं संगठनात्मक कार्यों में भाग नहीं लेता। बीजद विपक्षी दल की भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा है। पिछली विचारधारा वाली कोई पार्टी नहीं है। हमने पीएसी और अनुशासन समिति से पार्टी को संगठित करने के लिए कहा था, वह हो गया है। पार्टी में अन्य प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है। किसी ने मुझसे चर्चा नहीं की है या मैं किसी से नहीं मिला हूँ। श्री मलिक ने कहा, अभी नई बीजद बनाने का समय नहीं है, पुरानी को ठीक से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

सरायकेला पुलिस ने चोरी के सत्रह बाईक बरामद कर दस अपराधियों को किया गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला , सरायकेला-खरसावां पुलिस ने दो अलग-अलग वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी के कुल 17 मोटरसाइकिल और 1 पिकअप वाहन बरामद किए गए है ।

पहला गिरोह आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जहां से 8 मोटरसाइकिल और 1 पिकअप वाहन बरामद हुए। गिरफ्तार अपराधियों में सुजीत दास, लव मांझी, अजीत दास, भीम यादव, तरुण यादव, रासु गोराई, विलियम कुमार कर और शिवा दास शामिल हैं।

बरामद वाहनों में हीरो स्प्लेंडर प्लस, हीरो स्प्लेंडर, हीरो पासियन प्लस, बजाज पल्सर और टीवीएस जुपिटर जैसी बाइकें हैं।

दूसरा गिरोह कुचाई थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जहां से 9 मोटरसाइकिल बरामद हुए। गिरफ्तार/निरुद्ध व्यक्तियों में अमित कुम्भकार, उदय सामाड़ और 4 नाबालिग शामिल हैं। इस गिरोह के संबंध में कुचाई थाना कांड 41/25, गम्हरिया थाना कांड 97/25 और बिष्टुपुर थाना कांड 70/24 का उद्भेदन हुआ है। छापामारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

सनद रहे कि एस पी सरायकेला खरसावां ने 9 माह पहले कुचाई जंगली इलाके के दलभंगा ओपी क्षेत्र में अन्तर जिला गिरोह का पकड़ कर भांडाफोड करते हुए 70 बाईक बरामद की थी।

आत्मनिर्भर भारत का स्वर्णिम आधार: हिंदी

[हिंदी: हर भारतीय के सपनों को साकार करने की भाषा]

14 सितंबर का हिंदी दिवस वह आलोकित पड़ाव है, जब भारत का हृदय अपनी सबसे प्रखर और जीवंत धड़कन से समूचे विश्व को स्पंदित करता है। यह न केवल 1949 का वह ऐतिहासिक क्षण है, जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का गौरवपूर्ण दर्जा दिया, बल्कि 2025 का वह डिजिटल युग है, जहाँ हिंदी एक वैश्विक सुपरपावर के रूप में उभरी है। यह भाषा अब केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि एक ऐसी गतिशील शक्ति है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक एकता को नया आयाम दे रही है। हिंदी वह सेतु है, जो गाँव की मिट्टी से जुड़ी चौपाल को वैश्विक मंचों की ऊँचाइयों तक जोड़ता है, हर भारतीय को सशक्त और आत्मविश्वास से भरे भविष्य का सपना दिखाता है। यह लेख हिंदी की उन अनंत संभावनाओं को रेखांकित करता है, जो इसे भारत की प्रगति का प्रेरक इंजन और वैश्विक पहचान का चमकता प्रतीक बनाती हैं।

हिंदी की ताकत उसकी सर्वसमावेशी प्रकृति में निहित है—यह हर भारतीय को अपनी बोली में सपने बुनने और उन्हें साकार करने की हिम्मत देती है। 2025 में, जब भारत के 90 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे से अधिक हिंदी में डिजिटल कंटेंट की माँग कर रहे हैं, हिंदी ने डिजिटल जगत को सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक बना दिया है। एक ग्रामीण युवा, जो कभी अंग्रेजी की जटिलताओं से घबराता था, आज यूट्यूब पर हिंदी में खेती के नवोन्मेषी नुस्खे साझा कर लाखों तक पहुँच रहा है और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहा है। गूगल के हिंदी-सपोर्टेड एआई मॉडल्स ने सूचना को सहज और सुलभ बनाया है—"मौसम कैसा रहेगा?" जैसे सवालों के त्वरित हिंदी जवाब अब किसानों के लिए जीवन बदलने वाली जानकारी बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिंदी कंटेंट की लहर ने ब्रांड्स को ग्रामीण उपभोक्ताओं के दिलों तक पहुँचाया है—"अब खरीदें" जैसे साधारण शब्द स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। यह हिंदी की वह डिजिटल शक्ति है, जो भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक नई पहचान गढ़ रही है।

2025 में हिंदी शिक्षा का चेहरा बदल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हिंदी को नया आयाम दिया, और अब एआई टूल्स इसे साकार कर रहे हैं। टेक महिंद्रा का प्रोजेक्ट इंडस, एक हिंदी-केंद्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम), हर छात्र के लिए व्यक्तिगत और सरल पाठ्य सामग्री तैयार करता है। कल्पना करें, एक ग्रामीण बच्चा "प्रकाश संश्लेषण" को अपनी मातृभाषा में समझकर विज्ञान के प्रति जुनून जगाता है, न कि अंग्रेजी के "फोटोसिंथेसिस" से घबराता है। इंटरैक्टिव हिंदी ऐप्स ने साहित्य को रोमांचक बना दिया है—प्रेमचंद की कहानियाँ डिजिटल कहानी कहने के ज़रिए बच्चों की कल्पनाओं को पंख दे रही हैं। यह हिंदी की वह ताकत है, जो शिक्षा को समावेशी, प्रेरणादायक और हर बच्चे के लिए नवाचार का द्वार बना रही है।

वर्तमान में हिंदी, चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला रही है। ग्रामीण भारत, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ दुर्लभ हैं, वहाँ संयुक्त अरब अमीरात स्थित अग्रणी प्रौद्योगिकी होल्डिंग समूह जी42 का "नंदा" मॉडल हिंदी और इसकी बोलियों में संवाद कर मरीज़ों को सशक्त बना रहा है। यह "हृदय रोग" या "मधुमेह" को सरल शब्दों में समझाता है और टेलीमेडिसिन में रीयल-टाइम अनुवाद से संवाद को सहज बनाता है। भोजपुरी या अवधी बोलने वाला मरीज़ अब बेझिझक अपनी तकलीफ़ बता सकता है। हिंदी चैटबॉट्स गर्भवती महिलाओं को पोषण की सलाह देते हैं और बुजुर्गों को दवा का समय याद दिलाते हैं। कोविड-19 के बाद, हिंदी ने टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता को गाँव-गाँव तक पहुँचाया, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और समावेशी बनाया। यह हिंदी की वह शक्ति है, जो हर साँस को संरक्षित करने का ज़रिया बन रही है।

हिंदी भारत की सांस्कृतिक धड़कन बनकर उभरी है। यह भाषा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विविधता के सभी रंगों को एक ही माला में पिरोकर राष्ट्रीय एकता का अमिट प्रतीक बनी है। सोशल मीडिया पर यह केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति की प्रज्वलित मशाल है। जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा में भी हिंदी की गूंज और गहराई से सुनाई देती है—जहाँ गाँव की महिलाएँ अपनी मातृभाषा में बने छोटे-छोटे वीडियो से जल संरक्षण की प्रेरक कथाएँ रच रही हैं, जिन्हें दुनिया भर में सराहा जा रहा है। "समानता" और "स्वाभिमान" जैसे शब्द अब केवल शब्द नहीं, बल्कि हिंदी की शक्ति से प्रज्वलित चेतना की चिंगारी हैं, जो समाज को एक नई दिशा और दृढ़ संकल्प की ओर अग्रसर कर रही हैं।

हिंदी अब केवल भारत की सांस्कृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि आर्थिक उन्नति का एक प्रबल प्रेरक बन चुकी है। यह भाषा देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक शक्तिशाली यंत्र है, जो हर क्षेत्र में नवाचार और अवसरों को जन्म दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) 30% से अधिक का योगदान देते हैं, और इनमें से अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्रों से अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो इस भाषा की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है।उदाहरण के तौर पर, राजस्थान के एक छोटे से गाँव का मिट्टी का कारीगर अपनी बनाई अनूठी मूर्तियों को हिंदी में "हाथों की कला, दिल से दिल तक" जैसे आकर्षक नारे के साथ डिजिटल मंचों पर पेश करता है। यह नारा न केवल उसकी शिल्पकला को वैश्विक बाजार तक ले जाता है, बल्कि उसकी मेहनत और हिंदी की सांस्कृतिक गहराई को भी सम्मान देता है। यही हिंदी की आर्थिक ताकत है, जो एक साधारण कारीगर के सपनों को वैश्विक मंच पर साकार करती है। यह भाषा अब केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा सेतु है, जो ग्रामीण भारत के हुनर को विश्व व्यापार के साथ जोड़कर हर आकांक्षा को वास्तविकता में बदल रहा है।

2025 में हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की धड़कन बनकर उभरी है। यदि एआई केवल अंग्रेजी तक सीमित रहता, तो भारत की 60% आबादी प्रगति से वंचित रह जाती। लेकिन प्रोजेक्ट इंडस और नंदा जैसे मॉडल्स हिंदी को एआई का केंद्र बना रहे हैं। ये मॉडल्स न सिर्फ भाषा समझते हैं, बल्कि भारत की आत्मा को गहराई से छूते हैं—जैसे किसी किसान को उसकी अपनी बोली में "खाद सब्सिडी" की जानकारी देना। हिंदी एआई जलवायु मॉडलिंग में क्रांति ला रहा है, जो ग्रामीण भारत के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह हिंदी की वह शक्ति है, जो नवाचार का इंजन बनकर हर गाँव को भविष्य से जोड़ रही है।

झारखंड आईएएस आफसरों की पत्नियों का संगठन "जेसोवा" ने मुख्यमंत्री दंपति को किया आमंत्रित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन से आज उनके आवासीय कार्यालय में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (जेसोवा) के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने जेसोवा की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर - 2025 तक आयोजित होनेवाले दिवाली मेला में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को सपरिवार आमंत्रित किया। उन्होंने 5 दिनों तक चलने वाले इस दिवाली मेले के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने जेसोवा के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों कार्यक्रमों और गतिविधियों की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में जेसोवा की अध्यक्ष प्रीति कुमारी, सचिव मनु झा, कोषाध्यक्ष शिवानी सिंह, कार्यकारिणी समिति सदस्य रंजना कुमार एवं श्रीमती ज्योति मंजू शामिल थीं।

आग, आक्रोश और आशा: नेपाल का नया अध्याय

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने हाल ही में एक नाटकीय मोड़ लिया, जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह कदम जनरेशन जेड के युवा प्रदर्शनकारियों की जोशीली मांगों का परिणाम है, जिन्होंने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सामाजिक मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों ने देश को हिलाकर रख दिया—51 लोगों की जान गई, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया गया, और देशव्यापी कर्फ्यू लागू करना पड़ा। केपी शर्मा ओली की सरकार के इस्तीफे के बाद उठाया गया यह कदम नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। लेकिन सवाल यह है: क्या यह नियुक्ति नेपाल के लिए स्थायी स्थिरता ला पाएगी, या यह केवल अस्थायी राहत है?

सुशीला कार्की का चयन एक अभूतपूर्व प्रक्रिया का नतीजा है। 73 वर्षीय कार्की, जो 2016 से 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं, अपने न्यायिक सुधारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर रुख के लिए जानी जाती हैं। जेन जेड प्रदर्शनकारियों ने डिस्कॉर्ड ऐप पर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए उनका नाम चुना, जिसमें उन्होंने 31% वोट हासिल कर काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह (27%) को पछाड़ा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने संवैधानिक विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जेन जेड समूह की संसद भंग करने और छह महीने में नए चुनाव कराने की मांग को भी स्वीकार किया गया। युवाओं ने कार्की को ₹ईमानदार, निडर और दृढ़₹ बताते हुए उन्हें ₹राष्ट्र निर्माण का सशक्त विकल्प₹ करार दिया।

नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल में सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति एक उम्मीद की किरण है, लेकिन यह कितनी कारगर साबित होगी? कार्की की तटस्थता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अडिग रुख उन्हें जेन जेड प्रदर्शनकारियों की नजर में एक आदर्श विकल्प बनाता है। किसी राजनीतिक दल से न जुड़ी होने के कारण उनकी नियुक्ति निष्पक्षता का प्रतीक है, जो हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे नेपाल में ₹सुधारों की नई सुबह₹ का वादा करती है। 73 वर्षीय कार्की, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अपने कठोर न्यायिक सुधारों और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जानी जाती हैं। जेन जेड ने डिस्कॉर्ड पर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए उन्हें चुना, जो उनकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। उनकी भारत से गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव—विशेष रूप से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उनकी शिक्षा और भारत-नेपाल संबंधों के प्रति सकारात्मक रवैया—दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूती दे सकता है। एक साक्षात्कार में कार्की ने कहा, ₹मैं गंगा की यादों को संजोती हूं और भारत के योगदान को सम्मान देती हूं।₹ यह भारत के लिए एक अवसर है, खासकर तब, जब ओली सरकार के दौरान सीमा विवाद और चीन की बढ़ती उपस्थिति ने चिंताएं बढ़ाई थीं। कार्की की नियुक्ति नेपाल में जवाबदेही और पारदर्शी शासन की दिशा में एक साहसिक कदम हो सकती है।

लेकिन यह राह आसान नहीं है। कार्की के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। संवैधानिक प्रक्रिया में अस्पष्टता और संसद भंग करने के प्रावधान पर सहमति की कमी उनके लिए शुरुआती अड़चन है। प्रदर्शनों की आग में 51 से अधिक लोगों की जान गई, संसद और सरकारी भवनों को नष्ट किया गया, और 15,000 कैदियों के जेल से भागने ने अराजकता को बढ़ाया। सेना को कानून-व्यवस्था संभालनी पड़ी, जो अस्थिरता की गंभीरता को दर्शाता है। नेपाल, 2008 में राजतंत्र समाप्त होने के बाद से ही राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। युवा बेरोजगारी और विदेश पलायन जैसी समस्याओं ने जेन जेड के आक्रोश को हवा दी, जिन्होंने ₹नेपो किड्स₹ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्की को अब न केवल शांति बहाल करनी है, बल्कि आर्थिक सुधार और भ्रष्टाचार की जांच जैसे जटिल कार्य भी करने हैं। उनकी उम्र (73 वर्ष) और विशुद्ध न्यायिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नेतृत्व की जटिलताओं के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। 2017 में उनके खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव, भले ही जन दबाव में वापस ले लिया गया, उनकी राह में अविश्वास का सबब बन सकता है। यदि राजनीतिक दल सहयोग नहीं करते, तो यह अंतरिम सरकार एक और विफल प्रयोग बन सकती है। क्या कार्की इन तूफानों को पार कर नेपाल को स्थिरता की ओर ले जाएंगी, या यह नियुक्ति केवल एक अस्थायी पड़ाव है?

नेपाल का भविष्य अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति एक साहसी कदम है, लेकिन क्या यह देश को स्थायी स्थिरता की ओर ले जाएगा? यह अस्थायी समाधान जेन जेड के जोश और उनके ₹राष्ट्र निर्माण₹ के सपने को दर्शाता है, परंतु इसकी सफलता कई अनिश्चितताओं पर टिकी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राजनीतिक दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है, जबकि सेना की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने में निर्णायक होगी। जेन जेड ने छह महीने में नए चुनावों की घोषणा की है, जिसमें युवा अपने नेतृत्व का चयन करेंगे। इस बीच, कार्की की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच, आर्थिक सुधार और युवा रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है। कार्की की भारत-प्रेमी टिप्पणियां—जैसे गंगा की स्मृतियों और भारत के योगदान की प्रशंसा—नेपाल की विदेश नीति में बदलाव का संकेत देती हैं, जो ओली सरकार की चीन-केंद्रित नीतियों को संतुलित कर सकती हैं। उनके शब्द, ₹मेरा पहला कदम प्रदर्शनकारियों के परिवारों को न्याय और सहायता देना है,₹ दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया पर ₹जय नेपाल₹ और ₹नया अध्याय₹ जैसे उत्साहपूर्ण नारे गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं कि एकता और धैर्य जरूरी है, वरना अराजकता फिर लौट सकती है।

हालांकि, चुनौतियां कम नहीं हैं। संवैधानिक संशोधन की मांग और पुरानी राजनीतिक संरचनाओं से टकराव कार्की के लिए बड़ी बाधा है। नेपाल, जो भारत और चीन के बीच सामरिक रूप से स्थित है, को क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभावों से सावधान रहना होगा। आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी और विदेश पलायन जैसे मुद्दे जेन जेड के आक्रोश को भड़का सकते हैं। कार्की की नियुक्ति जेन जेड की लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनकी उम्र और न्यायिक पृष्ठभूमि राजनीतिक जटिलताओं से निपटने में अपर्याप्त साबित हो सकती है। यदि वह कानून-व्यवस्था बहाल कर निष्पक्ष चुनाव करा सकीं, तो यह नेपाल के लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन अगर राजनीतिक दल और युवा आंदोलन के बीच एकता टूटी, तो यह एक और संकट को जन्म दे सकता है। नेपाल को केवल राहत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत चाहिए। कार्की और जेन जेड की यह साझेदारी क्या इतिहास रचेगी, या यह एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी?

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

सोशल मीडिया पर नियंत्रण की बहस:फेक न्यूज़ से लेकर नेपाल के प्रतिबंध तक

हाल ही में भारतीय संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें फर्जी खबरों (फेक न्यूज) के प्रसार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। फेक न्यूज का मतलब है-जानबूझकर गढ़ी गई, झूठी या भ्रामक खबरें, जिन्हें इस तरह पेश किया जाता है कि वे सच जैसी लगें। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय, विचारधारा या राजनीतिक एजेंडे को लाभ पहुँचाना, भ्रम फैलाना, या जनमत को प्रभावित करना होता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज हमारे देश में फेक न्यूज की समस्या एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। फेक न्यूज की विशेषता यह होती है इसमें अक्सर झूठे और ग़लत तथ्य होते हैं तथा इसमें जानकारी या सूचनाएं वास्तविकता पर आधारित नहीं होती। खबरों को अक्सर तोड़-मरोड़ कर भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी न्यूज में अक्सर भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता है और आम आदमी में डर, नफरत, सनसनी या घृणा फैलाई जाती है, जो देश और समाज के लिए घातक सिद्ध होती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ए आइ का जमाना है और इस युग में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से फेक न्यूज बहुत तेजी से आम लोगों तक पहुँचती है। राजनीतिक लाभ, आर्थिक फायदा, गलत प्रचार, किसी व्यक्ति या समूह को बदनाम करना आदि फेक न्यूज का उद्देश्य हो सकता है। बहरहाल, यहां यह गौरतलब है कि समिति ने इस समस्या (फेक न्यूज) से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। पाठकों को बताता चलूं कि समिति ने सरकार से फर्जी खबरों की स्पष्ट कानूनी परिभाषा तय करने की मांग की है, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। समिति ने मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन, जुर्माने की राशि में वृद्धि और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है। यहां तक कि सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों में अनिवार्य रूप से तथ्य-जांच तंत्र और आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की है। संपादकों, सामग्री प्रमुखों, मालिकों और प्रकाशकों को संपादकीय नियंत्रण के लिए और प्लेटफार्मों को फर्जी खबरों के प्रसार के लिए जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता बताई गई है। सरकारी, निजी और स्वतंत्र तथ्य-जांचकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं, समिति ने ए.आई. के दुरुपयोग और महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित फर्जी खबरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। समिति की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है और इसे लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है। अगले संसद सत्र में इसे प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि समिति के अध्यक्ष, भाजपा सांसद ने इस संबंध में यह बात कही है कि भारत को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या थाईलैंड जैसा नहीं बनने देंगे, और जो लोग देश विरोधी ताकतों का एजेंडा चला रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जाएगी। वास्तव में, यह पहल फर्जी खबरों के प्रभावी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने में सहायक होगी। बहरहाल, समिति का यह मानना है कि फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन पर प्रतिबंध भी जरूरी है। गौरतलब है कि इन दिनों नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल, नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व में ट्विटर), और यूट्यूब—पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का इस संबंध में यह कहना था कि ये कंपनियां पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) में विफल रही हैं, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन) पर हमला मानते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विरोध प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में 19 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार काठमांडू और पोखरा में सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशनों, और नेताओं के घरों में आगजनी की गई और 13,500 से अधिक कैदी जेलों से फरार हो गए। हिंसा के बढ़ने के बाद, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया तथा नेपाल सेना ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू किया और प्रमुख सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी। बहरहाल , कहना ग़लत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण युवाओं ने सरकार के खिलाफ गुस्से का इज़हार किया। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आलीशान जीवनशैली की तुलना आम लोगों की कठिनाइयों से की, जिससे आक्रोश और बढ़ा। हालांकि, सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी है।कांतिपुर मीडिया समूह के कार्यालयों में आगजनी की गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मीडिया को सरकार का पक्षधर मानते हुए हमला किया। इसके बावजूद, पत्रकारों ने अपने घरों से अखबार प्रकाशित किए, जिससे प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा की।नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने युवाओं को सशक्त किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, और सामाजिक तनाव बढ़ा है। बहरहाल, यहां इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व 'जेन जी' कर रहा है। यह युवाओं का एक ऐसा समूह है, जो पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस समूह ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए सरकार के मंत्रियों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के बच्चों की फिजूलखर्ची तथा उनकी जीवनशैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें दोराय नहीं कि किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आजादी हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन क्या हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ ही इसका एकमात्र समाधान है? बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल की सरकार और युवा वर्ग देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और माहौल का शांत कर बातचीत की राह पर लौटेंगे। अंत में यही कहूंगा कि यह ठीक है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है, परंतु फेक न्यूज़ पर लगाम उससे भी अधिक आवश्यक है, ताकि सूचना विश्वसनीय और समाज जागरूक बना रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेस की स्वतंत्रता हर लोकतांत्रिक देश की पहचान है। एक स्वतंत्र मीडिया समाज को सही जानकारी देती है, यह भ्रष्टाचार उजागर करती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यही वजह है कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या वाच डॉग कहा जाता है ।आज के इस डिजिटल युग में फेक न्यूज़ या झूठी खबरें समाज में भ्रम, नफरत और तनाव पैदा कर देती हैं। कभी-कभी यह हिंसा, घृणा और अविश्वास का कारण बन जाती हैं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी व आवश्यक है कि प्रेस की स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारी भी बढ़े। वास्तव में, मीडिया को तथ्यों की पुष्टि कर ही समाचार प्रकाशित करना चाहिए। वहीं, नागरिकों को भी सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी खबर को बिना जांचे साझा नहीं करना चाहिए।स्वतंत्र प्रेस और सच की रक्षा-दोनों साथ चलें तभी समाज और देश मजबूत, जागरूक और प्रगतिशील बन सकता है। फेक न्यूज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर और बड़ा खतरा है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

इजराइल के हमले, अरब की नाराज़गी और भारत का संतुलन

राजेश जैन

इजराइल ने छह मुस्लिम देशों—गाजा (फिलिस्तीन), सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया—पर हवाई और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में २०० से अधिक लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों का बचाव करते हुए कहा कि इजराइल वही कर रहा है जो 9/11 के बाद अमेरिका ने किया था। यानी आतंकवाद को उसकी जड़ों तक जाकर खत्म करने की कोशिश। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। ऐसे समय में भारत के लिए यह सवाल और अहम हो जाता है कि उसे अपनी विदेश नीति किस तरह साधनी चाहिए।

भारत के सामने चुनौतियां

भारत के लिए यह घटनाक्रम सीधे असर डालने वाला है। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन पर टिकी रही है। एक तरफ इजराइल भारत का अहम रक्षा सहयोगी है, तो दूसरी तरफ अरब देश ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की वजह से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल, भारत अपनी कुल तेल ज़रूरतों का 85% आयात करता है, जिसमें से अधिकांश खाड़ी देशों से आता है। यदि यमन, कतर या सऊदी अरब में अस्थिरता बढ़ी तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी चुनौती खाड़ी देशों में रह रहे 80 लाख भारतीयों की सुरक्षा है। वहां संघर्ष बढ़ने पर उनकी जान और रोजगार दोनों संकट में आ सकते हैं।

तीसरी चुनौती रणनीतिक साझेदारी है। भारत-इजराइल रिश्ते डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, कृषि और टेक्नोलॉजी तक गहराई से जुड़े हैं, लेकिन ओआईसी के सदस्य देशों का दबाव भी भारत पर रहता है। चौथी चुनौती कूटनीतिक संतुलन की है। भारत ने परंपरागत रूप से फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन अब इजराइल से भी करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में भारत को तय करना होगा कि किस हद तक बयानबाजी करे और किस हद तक चुप रहे। पांचवीं चुनौती आतंकवाद का मुद्दा है। भारत इजराइल के आतंकवाद विरोधी रुख से सहानुभूति रख सकता है, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन में हो रहे मानवीय संकट को अनदेखा करने से भारत की छवि पर असर पड़ेगा।

भारत के विकल्प और विदेश नीति की दिशा

भारत के पास कई विकल्प हैं। सबसे पहले उसे मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और गाजा सहित अन्य प्रभावित देशों में हो रहे संकट पर चिंता जतानी चाहिए। इससे भारत की छवि एक संवेदनशील राष्ट्र की बनेगी। भारत शांति और मानवीय सहायता की पहल भी कर सकता है। दूसरा विकल्प ऊर्जा आपूर्ति का प्रबंधन है। भारत को अमेरिका, रूस और अफ्रीका जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देना होगा और घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा पर भी निवेश बढ़ाना होगा ताकि ऐसे संकटों का असर कम हो। तीसरा रास्ता बहुपक्षीय मंचों का उपयोग है। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और जी-२० जैसे मंचों पर भारत को संतुलित भूमिका निभानी चाहिए। न इजराइल का खुला समर्थन और न मुस्लिम देशों का अंधा विरोध, बल्कि संवाद और मध्यस्थता की पेशकश ही भारत को जिम्मेदार शक्ति बनाएगी। चौथा कदम प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा योजना बनाना होगा। भारत को पहले से तैयारी करनी होगी कि यदि खाड़ी देशों में हालात बिगड़ते हैं तो वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। पांचवां विकल्प रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देना है, जिससे यह संदेश जाए कि भारत की विदेश नीति अमेरिका या किसी और शक्ति से प्रभावित नहीं है बल्कि अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक शांति पर केंद्रित है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर असर

इजराइल और मुस्लिम देशों का टकराव नया नहीं है, लेकिन हाल के हमले एक बड़े संघर्ष की भूमिका लिखते दिख रहे हैं। खासकर इसलिए कि इसमें छह देश सीधे प्रभावित हुए हैं और यह महज़ इजराइल-फिलिस्तीन विवाद तक सीमित नहीं रहा। कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिससे युद्धविराम की कोशिशें नाकाम हो गईं। लेबनान में हिजबुल्लाह पर कार्रवाई से पहले से मौजूद सीजफायर टूट गया। सीरिया, जो पहले से अस्थिरता और गृहयुद्ध जैसी स्थिति झेल रहा है, वहां इजराइल के हमले हालात को और बिगाड़ देंगे। यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले से सऊदी अरब और अमेरिका के साथ उनके तनाव और गहरे होंगे। ट्यूनीशिया में भले ही सीधा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उत्तरी अफ्रीका तक संघर्ष की लपटें फैलने का खतरा है। गाजा की स्थिति सबसे भयावह है, जहां 150 से अधिक मौतें और सैकड़ों घायल हुए हैं और पहले से तबाह इलाका पूरी तरह संकट में है।

इन हमलों ने वैश्विक स्तर पर दो ध्रुवों को और तेज़ कर दिया है—एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ मुस्लिम जगत और उनके समर्थक देश। यूरोप भी असमंजस में है क्योंकि मानवीय संकट पर उसे चुप रहना मुश्किल हो रहा है, जबकि चीन और रूस इस मौके का फायदा उठाकर मुस्लिम देशों के करीब जाने की कोशिश करेंगे। इजराइल के ताज़ा हमलों ने दुनिया को फिर से याद दिलाया है कि पश्चिम एशिया वैश्विक राजनीति का सबसे अस्थिर इलाका है। यहां की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनीति को हिला देती है। भारत जैसे उभरते वैश्विक खिलाड़ी के लिए यह जरूरी है कि वह इस अस्थिरता में संतुलित, संवेदनशील और रणनीतिक विदेश नीति अपनाए। न इजराइल को पूरी तरह गले लगाना सुरक्षित है और न ही अरब देशों को नाराज़ करना। भारत का हित इसी में है कि वह शांति, संवाद और मानवीय मूल्यों का झंडाबरदार बने। यह घटनाक्रम भारत की विदेश नीति के सामने एक बड़ा सबक लेकर आया है—भू-राजनीति की आग में खुद को जलाए बिना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए दुनिया में एक जिम्मेदार ताकत की भूमिका निभाना। यही भारत की असली परीक्षा है और यही उसका आने वाला रास्ता।

दुनिया भर में बदल रहे हालात, अब मोटापे से जूझ रहा हर दसवां बच्चा, 39 करोड़ बच्चे बढ़ते वजन से परेशान

पुनीत उपाध्याय

अभी तक बच्चों में कुपोषण की ही चर्चा होती थी लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं।

एक ओर जहां बच्चों की बड़ी आबादी कुपोषण का दंश झेल रही है वहीं कड़वा सच यह भी है कि बाजारवाद के इस युग में बच्चे अपनी खराब फूड हैबिट के कारण मोटापे के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने फीडिंग प्रॉफिट-हाउ फूड एनवायरमेन्टस आर फेलिंग चिल्ड्रन शीर्षक से वर्ल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 जारी की है जो यह बताती है कि दुनिया भर में हर दसवां बच्चा मोटापे से जूझ रहा है। 39 करोड़ बच्चे बढ़ते वजन से परेशान हैं। 18.8 करोड़ बच्चे बढ़ते मोटापे से त्रस्त हैं। इतिहास में पहली बार है जब दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में मोटापे का स्तर कुपोषण के सबसे आम रूप यानी कम वजन से जूझ रहे बच्चों से ज्यादा हो गया है। 2000 से अब तक उन बच्चों ;(पांच से 19 वर्ष) की संख्या घटी है जो कम वजन से जूझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोटापे से पीड़ति बच्चों की संख्या में तीन गुणा इजाफा हुआ है और उनकी संख्या तीन फीसदी से बढ़कर 9.4 फीसदी पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट के अनुसार पहले बच्चे खाने की कमी, नाटेपन, घटते वजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। अब इसकी जगह मोटापे और बढ़ते वजन ने ले ली है। रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आज दुनिया का हर दसवां बच्चा (5 से 19 वर्ष) मोटापे से जूझ रहा है, यानी करीब 18.8 करोड़ बच्चे बढ़ते मोटापे से त्रस्त हैं। यह स्थिति उन्हें गंभीर और जानलेवा बीमारियों के खतरे में डाल रही है। इन बच्चों में मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल के अनुसार मोटापा एक बढ़ती समस्या है जो बच्चों की सेहत और मानसिक एवं शारीरिक विकास को खतरे में डाल रहा है। रिपोर्ट में इस तथ्य को भी उजागर किया गया है कि 2000 से अब तक उन बच्चों (पांच से 19 वर्ष) की संख्या घटी है जो कम वजन से जूझ रहे थे। इन बच्चों का आंकड़ा 13 फीसदी से घटकर 9.2 फीसदी रह गया है। मोटापे से पीड़ति बच्चों की संख्या में तीन गुणा इजाफा हुआ है और उनकी संख्या तीन फीसदी से बढ़कर 9.4 फीसदी पर पहुंच गई है। इसक मतलब है कि यदि उप.सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया को छोड़ दें तो अब दुनिया के सभी हिस्सों में मोटापे से जूझ रहे बच्चों की गिनतीए कम वजन वाले बच्चों की संख्या से आगे निकल गई है। प्रशान्त द्वीप समूह में यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है जहां पारम्परिक आहार की जगह सस्ते, ऊर्जा.सघन आयातित खाद्य पदार्थों ने ले ली है।

याददाश्त और सीखने की क्षमता होती है प्रभावित

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बच्चों को तब अधिक वजन वाला माना जाता है जब उनका वजन अपनी उम्र, लिंग और ऊंचाई के हिसाब सेए स्वस्थ वजन वाले बच्चों से काफी अधिक होता है। मोटापा अधिक वजन से जुड़ी अवस्था का ही एक गम्भीर रूप है और इससे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेन्स और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि दुनिया में पांच से 19 वर्ष के करीब 39.1 करोड़ बच्चे बढ़ते वजन से जूझ रहे हैं। मतलब की हर पांचवां बच्चा इस समस्या से पीड़ति है। इनमें से करीब आधे बच्चे मोटापे की चपेट में हैं। देखा जाए तो यह समस्या आगे चलकर बच्चों में मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की वजह बन सकती है।

फास्ट फूड कंपनियों का मुनाफा, दांव पर बच्चों की जिंदगी

रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की सेहत पर बाजार की ताकतें हावी हो रही हैं। चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा से भरे अल्ट्रा.प्रोसेस्ड और फास्ट फूड उनके खाने पर काबिज हो रहे हैं। इनका आक्रामक प्रचार बच्चों को और भी ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है। यूनीसेफ ने 170 देशों के 64 हजार से ज्यादा युवाओं पर एक सर्वेक्षण किया था।

परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने डायट फारबिसगंज के प्राचार्य आफताब आलम को शिक्षा भूषण सम्मान 2025 से किया सम्मानित

अररिया। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, बिहार की ओर से डायट फारबिसगंज के प्राचार्य आफताब आलम को शिक्षा भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह पर्यटन मंत्री, बिहार सरकार श्री राजू कुमार सिंह एवं महासंघ के प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। महासंघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सह प्रधान शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने मोमेंटो एवं अंगवस्त्र प्रदान कर प्राचार्य आलम का सम्मान किया। इस अवसर पर श्री अशोक कुमार ने कहा कि डायट फारबिसगंज के प्राचार्य ने संस्था की बेहतरीन व्यवस्था, कुशल प्रबंधन एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन्हीं कारणों से उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से गोपाल जी, रवि कुमार, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अजहर, ऋषिकांत निगम, विनोद कुमार, रंजन कुमार, रंजेश कुमार सहित सैकड़ों प्रशिक्षु प्रधान शिक्षक उपस्थित रहे।

आज से फसलों की गिरदावरी में राजस्व विभाग का अमला पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगा : धालीवाल

मान सरकार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए वचनबद्ध : धालीवाल

अमृतसर/अजनाला, (साहिल बेरी)

हलका विधायक और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि 13 सितम्बर से हलका अजनाला सहित पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नष्ट हुई फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों और बाढ़ के कारण मरे पशुओं के लिए प्रभावित पात्रों को सरकारी मुआवज़ा देने हेतु मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सर्वे/गिरदावरी शुरू करवाई जा रही है। इस कार्य के लिए नियुक्त राजस्व विभाग के अमले सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से ज़िम्मेदारियाँ निभाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित बाढ़ पीड़ितों का हक़ मारने या किसी राजनीतिक प्रभाव तथा निजी लालच में किसी को अनुचित लाभ पहुँचाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रभाव में किया गया भ्रष्टाचार अपने ही परिवार को ज़हर खिलाने के बराबर है। छोटे-बड़े राजनीतिक नेताओं द्वारा बाढ़ पीड़ितों के नाम पर मुआवज़े की राशि हड़पने का खामियाज़ा भी एक दिन जान-माल की हानि और बीमारी के रूप में भुगतना ही पड़ेगा।

श्री धालीवाल ने यह विचार उस समय प्रकट किए जब वे बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित सरहदी और रावी नदी के नज़दीकी गाँव नंगल सोहल पहुँचे। यहाँ एस.डी.एम. अजनाला श्री रविंदर सिंह अरोड़ा की अगुवाई में ज़िला प्रशासन द्वारा 359 लाभार्थियों को राहत सामग्री की किटें, मंज़े और गद्दे वितरित किए गए। इस मौके पर श्री गुरु कलगीधर ट्रस्ट, बड़ू साहिब ने भी सहयोग दिया। इसी प्रकार प्रभावित गाँव हरड़ खुर्द में भी लगभग 100 लाभार्थियों को कंबल, मंज़े आदि सामग्री ब्लॉक प्रधान और सरपंच लवप्रीत सिंह हरड़ तथा समाजसेवियों के सहयोग से बाँटी गई।

श्री धालीवाल ने कहा कि मान सरकार ने यह लक्ष्य तय कर लिया है कि अक्टूबर महीने के मध्य तक गिरदावरी और अन्य नुकसानों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा और दीवाली त्यौहार तक मुआवज़े के चेक प्रभावित पीड़ितों के हाथों में पहुँचा दिए जाएँगे। उन्होंने दावा किया कि मान सरकार के निर्देशों के तहत पहले चरण में हलका अजनाला के 100 प्रभावित गाँवों में प्रशासन और समाजसेवियों के सहयोग से बाढ़ के पानी में फँसे 3200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। दूसरे चरण में पानी से घिरे घरों की छतों पर दिन गुज़ार रहे सैकड़ों भूखे-प्यासे लोगों तक भोजन पहुँचाकर उन्हें नया जीवन दिया गया। वर्तमान में भी लगातार बाढ़ पीड़ितों को उनकी ज़रूरत अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है और अब 13 सितम्बर से प्रभावित फसलों की गिरदावरी शुरू होने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मान सरकार इस संकट की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए वचनबद्ध है।

'स्वास्थ्य पर चर्चा': अमृतसर में अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने जागरूकता पर दिया जोर

अमृतसर, 12 सितम्बर (साहिल बेरी)

इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने अमृतसर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सहयोग से 'स्वास्थ्य पर चर्चा' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कुँवर विजय प्रताप सिंह (माननीय विधायक, उत्तर अमृतसर) उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को समय पर जांच, शीघ्र निदान और जीवनशैली में सुधार की महत्ता के प्रति जागरूक करना था ताकि क्रॉनिक और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के मामलों में कमी लाई जा सके।

कार्यक्रम में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों डॉ. (प्रो.) संजीव जसुजा (नेफ्रोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट), डॉ. वनीता अरोड़ा (कार्डिएक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एवं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी), डॉ. योगेश बत्रा (गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं हेपेटोलॉजी) और डॉ. गौरव त्यागी (न्यूरोसर्जरी) ने लोगों को किडनी स्वास्थ्य, हृदय रोगों की रोकथाम, पाचन तंत्र की देखभाल और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य पर कई अहम जानकारियां साझा की।

यह आयोजन अमृतसर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ए.पी.एस. छठा और उपाध्यक्ष एवं सचिव श्री पीयूष कपूर की उपस्थिति में हुआ। दोनों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में ऐसे अभियानों को समुदाय तक पहुंचाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने कार्यक्रम के दौरान अपोलो प्रिविलेज हेल्थ कार्ड एसोसिएशन को भेंट किया। यह कदम अस्पताल की सामुदायिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य अतिथि श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह (माननीय) विधायक उत्तर, अमृतसर ने कहा, "स्वास्थ्य पर चर्चा एक स्वस्थ समुदाय बनाने की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम है। निवारक स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता को जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए ताकि हमारे लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकें और शुरुआती चरण में ही बीमारियों का पता लगा सकें।" उन्होंने यह भी कहा, "मैं हमारे शहर में इस महत्वपूर्ण पहल को लाने के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल और अमृतसर होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन की सराहना करता हूं।"

कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के नेफ्रोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. (प्रो.) संजीव जसुजा ने किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में कहा, ₹पुरानी गुर्दे की बीमारी आमतौर पर तब तक अज्ञात रहती है जब तक कि यह अच्छी तरह से विकसित नहीं हो जाती। क्रॉनिक किडनी डिजीज अक्सर देर से पकड़ में आती है। नियमित स्वास्थ्य जांच, मधुमेह और रक्तचाप नियंत्रण और प्रारंभिक जांच से गुर्दे की विफलता और डायलिसिस या प्रत्यारोपण की आवश्यकता को रोका जा सकता है।" वहीं क्लिनिकल लीड-कार्डिएक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और कार्डिएक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट व इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. वनिता अरोड़ा ने कहा, "आजकल युवा वर्ग में हार्ट रिद्म डिसऑर्डर और हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। नियमित व्यायाम, सही खानपान और समय-समय पर हृदय जांच जरूरी है।"

गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश बत्रा ने आंत के स्वास्थ्य पर जीवन शैली और आहार के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए कहा, ₹भारत में मोटापा, शराब और प्रसंस्कृत भोजन से जुड़े यकृत और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों में वृद्धि देखी जा रही है। निवारक देखभाल, टीकों और प्रारंभिक निदान के साथ मिलकर, दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभों को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है।" इनके अलावा न्यूरो सर्जरी विभाग के सलाहकार डॉ. गौरव त्यागी ने हाल ही में उभरते न्यूरोलॉजिकल परेशानियों पर जानकारी देते हुए कहा, ₹स्ट्रोक और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं जैसी

तंत्रिका संबंधी स्थितियां अब बहुत कम उम्र में हो रही हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप, नियमित निवारक स्वास्थ्य जांच और चेतावनी संकेतों के प्रति सतर्कता जैसे अचानक सिरदर्द या कमजोरी, जीवन बचा सकते हैं।"

कार्यक्रम में अमृतसर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ए. पी. एस. चठा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, ₹हमें 'स्वास्थ्य पर चर्चा' के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। निवारक स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता पैदा करना समय की आवश्यकता है, और हम इस तरह की सार्थक बातचीत को समुदाय तक ले जाने में अपना समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अमृतसर होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सचिव श्री पीयूष कपूर ने कहा, ₹आतिथ्य क्षेत्र रोजाना हजारों लोगों के साथ बातचीत करता है, और हम मानते हैं कि स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की पहल न केवल जागरूकता फैलाती है बल्कि लोगों को सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी प्रेरित करती है।"

दरअसल यह कार्यक्रम भारत में निवारक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने, सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल आदतों को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष डॉक्टरों, स्थानीय प्रभावकों और सामुदायिक नेताओं को शामिल करने के लिए अपोलो अस्पताल के समर्पण पर प्रकाश डालता है। 'स्वास्थ्य पर चर्चा' जैसे कार्यक्रम ने डॉक्टरों, होटल उद्योग और समुदाय के बीच एक सेतु का काम किया। इस तरह के कार्यक्रम न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में

इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स, भारत का पहला जेसीआई (JCI) मान्यता प्राप्त अस्पताल, दिल्ली सरकार और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। जुलाई 1996 में स्थापित यह अपोलो समूह का तीसरा सुपर-स्पेशलिटी टर्शियरी केयर अस्पताल है। 15 एकड़ में फैला यह अस्पताल 57 विशिष्टताओं के साथ काम करता है, जहां 300 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और 700 से ज्यादा ऑपरेशनल बेड उपलब्ध हैं। यहां 19 ऑपरेशन थिएटर, 138 आईसीयू बेड, 24×7 फार्मेसी, NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं, आपातकालीन सेवाएँ और सक्रिय एयर एम्बुलेंस सुविधा मौजूद है। अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली देश का अग्रणी किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाता है। भारत में पहली सफल पीडियाट्रिक और एडल्ट लिवर ट्रांसप्लांट यहीं किए गए थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023